कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

वैशाख–ज्येष्ठ 2077, मई 2020

VOICE OF SELF RELIANT INDIA

SWADESHI Patrika

स्वदेशी पत्रिका

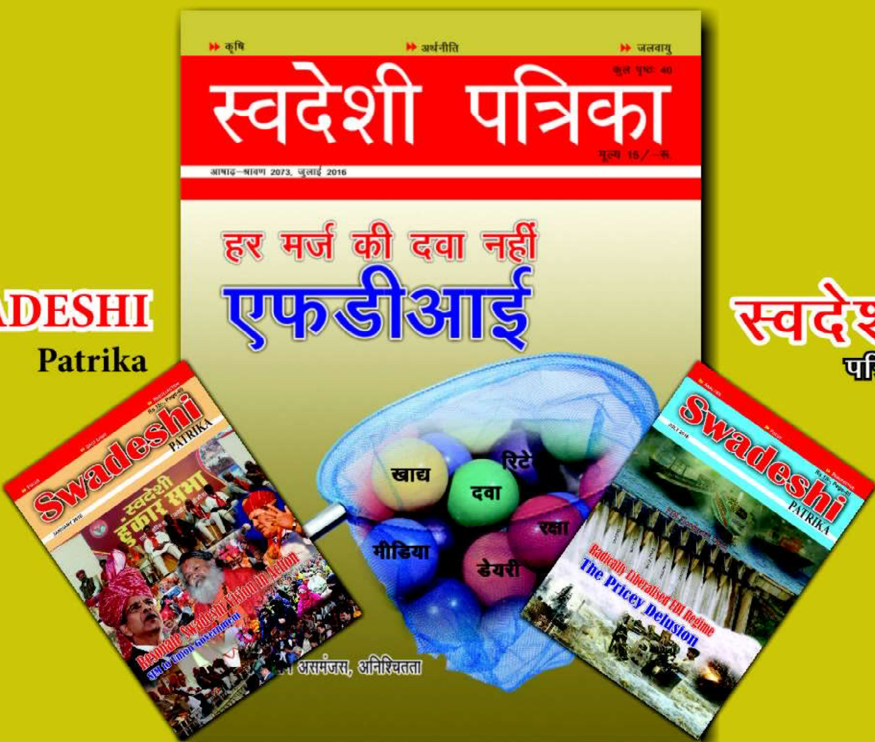

वार्षिक सदस्यता **(Annual Subscription) :**	**150/-**
आजीवन सदस्यता **(Life Membership) :**	**1500/-**

For subscription please send payment by A/c payee Cheque/Demand Draft/Money Order in favour of 'Swadeshi Patrika' at New Delhi, or Deposit the subscription amount in

Bank of India, *A/c No.* **602510110002740,**
IFSC: BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

Kindly write your full name and address in capital letters.
If you do not receive any issue of Swadeshi Patrika, kindly e-mail us immediately or contact **Sh. Suraj Bhardwaj (9899225926)**

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–28, अंक–5

वैशाख–ज्येष्ठ 2077 मई 2020

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**

समाचार परिक्रमा **35-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–6

चीन से परहेज करती दुनिया

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा-2
कोरोना के आगे है कामयाबी .... अनिल तिवारी

10 आवरण कथा-3
कोरोना के कहर में कैसे दें चीन को मात .... डॉ. भरत झुनझुनवाला

12 विचार
आत्मनिर्भर मॉडल ही महामारी के मकड़जाल से निकलने का महामंत्र .... कश्मीरी लाल

14 आजकल
आर्थिक नीतियों की समीक्षा का समय .... दुलीचन्द कालीरमन

16 पहल
कोरोना से लड़ेंगें भी और जीतेंगे भी .... डॉ. निरंजन सिंह

18 मुद्दा
वैक्सीन क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा जरूरी .... भारत डोगरा

20 आजकल
महामारियों ने बदला है इतिहास .... सूर्यप्रकाश अग्रवाल

23 जन्मशताब्दी वर्ष
ठेंगडी जी के विचारों में है भारत के आर्थिक विकास का सूत्र .... श्रीनिवास

25 जल प्रबंधन
कोरोना महामारी एवं जल संकट .... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

27 पृथ्वी दिवस
पृथ्वी दिवस की प्रतिज्ञाः स्थायी और स्वदेशी पुनर्जीवन .... इन्द्र शेखर सिंह

29 दृष्टिकोण
कोरोना संकट एवं भारतीय संस्कृति .... डॉ. अजित कुमार

31 बहस
देश में मजदूरी दर में भिन्नता क्यों? .... डॉ. जयप्रकाश मिश्र

पाठकनामा

स्वदेशी थीम वाले विज्ञापनों की भरमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी पर जोर देने के बाद बड़ी उपभोक्ता कंपनियां अपने सभी विज्ञापन और मार्केटिंग कैंपेन में वोकल फॉर लोकल पर जोर बढ़ा रही हैं। आईटीसी पारले प्रोडक्ट्स, अमूल डावर, गोदरेज, मैरिको और वोल्टास जैसी कंपनियों ने इस दिशा में कदम उठाया है।

इस दिशा में डाबर कंपनी ने स्वदेशी के संदेश के साथ डिजिटल मीडिया और टीवी खासतौर से न्यूज़ चैनल पर विज्ञापन देना शुरू किया है। वाटिका शैंपू और रेड टूथपेस्ट बनाने वाली डाबर का मुकाबला कोलगेट पामोलिव और हिंदुस्तान युनिलीवर लिमिटेड सरीखी मल्टीनैशनल कंपनियों से है। बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात की काफी संभावना है कि मेड इन इंडिया फैक्टर का लोगों के खरीदारी करने के निर्णय पर यकीनन असर पड़ेगा। वोकल फॉर लोकल कैंपेन में आयुर्वेद सरीखे भारत के परंपरागत ज्ञान का फायदा उठाने की क्षमता है। आत्मनिर्भर भारत की थीम वाले अपने संबोधन में पीएम ने लोगों से स्थानीय उत्पादों और ब्रांड पर जोर देने की अपील की थी और देश में बनाए गए उत्पाद खरीदने को कहा था।

सिगरेट से लेकर कंज्यूमर गुड्स तक बनाने वाली आईटीसी ने कहा है कि वह अपने कैंपेन में मेक इन इंडिया पर जोर देगी। आशीर्वाद आटा, सनफिश बिस्किट और विवेल साबुन बनाने वाली आईटीसी ने अपने गैर सिगरेट कारोबार से बड़ी बिक्री हासिल करने का लक्ष्य रखा। कंपनी ने 25 तरह के इंडियन ब्रांड बनाए हैं। कंपनी का दावा है कि इससे बड़े पैमाने पर लोगों को आजीविका हासिल होगी। देश की सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी पारले प्रोडक्ट्स ने पारले–जी व हाइड एंड सिक जैसे कई बड़े ब्रांड के लिए स्वदेशी थीम वाले विज्ञापन तैयार किए हैं। पारले प्रोडक्ट्स खुद को स्वदेशी ब्रांड बताने के लिए सभी प्लेटफार्म का उपयोग कर रहा है। मालूम हो कि देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल पिछले तीन दशकों से भी इस थीम पर काम कर रहा है।

***संजय कुमार**, देवली (दिल्ली)*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

विकास का एक नया मॉडल बनाना होगा। देश को स्वदेशी आधारित मॉडल पर जाना होगा। भारत को दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी।

डॉ. मोहन भागवत (सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ)

विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन, आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है।

नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री, भारत)

चीन के साथ हमारे संबंध तब तक अच्छे थे, जब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया।

डोनाल्ड ट्रंप (राष्ट्रपति, अमरीका)

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली (डब्ल्यूटीओ) में उथल-पुथल का और सबूत। डब्ल्यूटीओ प्रमुख ने दिया इस्तीफा। यह भारत और अमरीका में लोकलाईजेशन की लहर का परिणाम तो नहीं?

डॉ. अश्वनी महाजन (राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच)

लोकल के लिए वोकल

भारत के लिए एक नया सूर्योदय

'आत्मनिर्भर भारत मिशन' का कौन समर्थन नहीं करेगा? यह विचार भारतीय लोकाचार और जन सामान्य से सीधे जुड़ा हुआ है। ब्रिटिशों को हराने के लिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी के विचार का इस्तेमाल किया था, और उनके लिए स्वदेशी, आत्मनिर्भरता की ही अभिव्यक्ति थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 मई 2020 के 30 मिनट के राष्ट्रव्यापी संबोधन को एक गांधी के विचार को अपनाते हुए एक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय को बढ़ावा देने के मार्ग पर चलने का संकल्प है।

दुनिया के विकसित देश दूसरे देशों के विकास मॉडल की नकल करके विकसित नहीं हुए। उन्होंने खुद को विकसित करने के लिए अपनी रणनीतियों को स्वयं तैयार किया। लेकिन हमारे नीति निर्माता तो विदेशी मॉडलों से अभिभूत रहे और उन्होंने कभी भी लोगों की क्षमता पर भरोसा ही नहीं किया, न ही लोकाचार, विचार प्रक्रिया और न ही इस देश के लोगों की उद्यमशीलता की क्षमता पर भरोसा किया।

वर्ष 1950 के बाद से, जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में नीति निर्माताओं ने विकास के रूसी मॉडल पर विश्वास किया। इस मॉडल को नेहरू–स्टालिन मॉडल भी कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र आधारित दर्शन इस मॉडल के मूल में था। यह सोचा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र इस देश के विकास को गति देगा, और अंतोत्गत्वा उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों के विकास में भी वहीं योगदान देगा। लेकिन उस मॉडल में कृषि और सेवा क्षेत्र को कोई स्थान नहीं दिया गया। अचानक, 1991 में यह महसूस किया गया कि जिस मॉडल पर हमारी अर्थव्यवस्था आधारित थी वह विफल रहा है। बढ़ते विदेशी ऋण के कारण देश मुसीबत में आ गया, विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गये थे और संप्रभु कोताही (डिफॉल्ट) का खतरा उत्पन्न हो गया था। यह कहा गया कि अर्थव्यवस्था को बचाने का एकमात्र तरीका वैश्वीकरण (वाशिंगटन की सहमति के आधार पर) को अपनाना ही है। हमने देश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), बहुराष्ट्रीय निगमों, यानी विदेशियों के हाथ सौंप दिया। यह नई व्यवस्था पूंजी पर आधारित थी और वह भी विदेशी पूंजी पर आधारित। एकाधिकार और बाजार पर कब्जा करना बड़ी विदेशी कम्पनियों की प्राथमिकता थी। इस मॉडल के बचाव में यह तर्क दिया गया कि इसके कारण ग्रोथ में तेजी आई। लेकिन यह ग्रोथ रोजगार विहीन, जड़विहीन और सब से ऊपर बेरहम थी।

एक तरफ अंधाधुंध रियायतें देकर हमारी पहले से ही अच्छी तरह से चलने वाली कंपनियों का अधिग्रहण विदेशी पूंजी को करने की छूट दे दी और दूसरी तरफ वैश्वीकरण के नाम पर चीनी माल के आयात की अनुमति देकर, हमने अपने देश में रोजगार को नुकसान पहुँचाने का काम किया और आर्थिक असमानताओं को बढ़ाने का काम किया। विदेशी व्यापार और और चालू खाते पर भुगतान शेष में घाटा असहनीय होता गया। इसी का परिणाम था। इस तरह के बेलगाम भूमंडलीकरण ने कई स्थानीय उद्योगों को तहस नहस कर दिया। इसका सीधा परिणाम स्थानीय विनिर्माण, रोजगार का नुकसान और शहरी श्रमिक वर्ग और ग्रामीण आबादी की गरीबी था, क्योंकि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) नीतियों में पूरी तरह से ध्यान से बाहर थी। बेरोजगारी और गरीबी ने लोगों को सरकारी मदद पर निर्भर बना दिया। उन्हें समाज के लिए मूल्यवान योगदान करने वाला बनाने के बजाय, सरकारी सहायता पर निर्भर बना दिया गया।

हम कह सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी का लोकल के लिए जोर, जिसे 'वोकल फॉर लोकल' कहा जा रहा है, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है, जिसकी लंबे समय से जरूरत थी। आज उन स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने का समय है जो वैश्वीकरण के युग में नष्ट हो गए। यह उन आर्थिक नीतियों की शुरूआत करने का भी समय है जो जन कल्याण, स्थायी आय, रोजगार सृजन और सभी के लिए मददगार हो और जो लोगों में विश्वास पैदा करें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सामाजिक क्षेत्रों की दुखद स्थिति स्वास्थ्य और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय की कमी के कारण भी है। दुर्भाग्यपूर्ण तो यह रहा कि इन कल्याणकारी क्षेत्रों को निजी मुनाफे के लिये सौंपा जाने लगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऐतिहासिक भाषण के साथ, भारत के लिए न केवल 'क्वांटम जंप' यानि लंबी छलांग लेने की नींव रखी, बल्कि स्वदेशी उद्यमियों के लिए अधिक अवसर और सम्मान भी पैदा करने की ओर कदम बढ़ाया है। स्थानीय उद्योगों के लिए मुखर होने का प्रधानमंत्री का आह्वान स्वागत योग्य हैं।

इस बीच चीनी वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा, जो जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत है, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, लघु उद्यमियों, किसानों के साथ अति सूक्ष्म उद्यमों, ईमानदार कर दाताओं और अन्य व्यवसायों के लिए राहत और अवसर दे सकती है। इसलिए इस अवसर का उपयोग स्थानीय विनिर्माण और अन्य व्यवसायों के आधार पर अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। यह देश को और अधिक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा।

चीन से परहेज करती दुनिया

पिछले 20 वर्षों से वैश्विक बाजार में धूम मचाने वाला और वैश्विक निवेशकों का चहेता चीन आज न केवल निवेशकों की बेरुखी झेल रहा है, बल्कि पहले से स्थापित विदेशी कंपनियां चीन से कूच की तैयारी कर रही हैं। जापान सरकार ने अपनी कंपनियों को 2 अरब डॉलर की मदद देने का फैसला लिया है जो चीन से कूच कर रही हैं, ताकि वे आसानी से इस काम को अंजाम दे सके। दुनिया भर की लगभग 1000 कंपनियों ने तो भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और निकायों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, जो चीन से अपना कारोबार समेट भारत की ओर रुख करना चाहती हैं।

उधर पिछले लगभग एक दशक में अपने विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक शक्ति के बलबूते चीन की सरकार और कंपनियों ने दुनिया भर में भारी निवेश करना शुरू कर दिया। विश्व भर में चीनी सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों ने बड़ी संख्या में कंपनियों का अधिग्रहण ही नहीं किया, बल्कि अफ्रीका समेत कई मुल्कों में उन्होंने बड़ी मात्रा में भूमि भी खरीद ली। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में वन बेल्ट वन रोड परियोजना के अंतर्गत चीन की सरकार, सरकारी कंपनियों और निजी कंपनियों ने भारी मात्रा में संरचनात्मक ढांचे में निवेश करना शुरू कर दिया। दुनिया के 65 से ज्यादा देशों को यह कहकर कि इस परियोजना से न केवल उनके संरचनात्मक ढांचे का विकास होगा, वे दुनिया के सबसे बड़े सड़क मार्ग रेलमार्ग जलमार्ग का हिस्सा भी बनेंगे, दुनिया के मुल्कों को कर्ज जाल में फँसाया गया। उनको बिजली उत्पादन और वितरण में भी सुधार का आश्वासन दिया गया। ऐसी बड़ी परियोजनाओं की योजना की गई जिसकी व्यवसायिक आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन उस पर किया गया खर्च उन देशों पर कर्ज को बढ़ाता चला गया। चीन की कंपनियों को ठेके मिले और चीनी कार्मिकों को काम मिला लेकिन उन मुल्कों को मिला तो केवल कर्ज का बोझ। ऐसा बोझ जो वे उतार ही न पायें। श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह का निर्माण चीन की इस कर्ज जाल नीति का एक बड़ा उदाहरण बन गया। पूरा विश्व जानता है कि

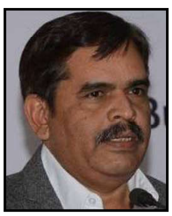

दुनिया भर में चीन के प्रति गुस्से और उसके कुत्सित प्रयासों के खिलाफ बढ़ती जागृति के चलते भविष्य में चीन के दूसरे मुल्कों के साथ आर्थिक संबंध पूर्व जैसे नहीं रहेंगे। ऐसा लगता है कि चीन ने पिछले 20 सालों में भूमंडलीकरण का जो लाभ उठाया है उसके आगे का रास्ता सुगम रहने वाला नहीं।

– डॉ. अश्वनी महाजन

हंबनटोटा बंदरगाह का निर्माण चीन ने किया और कर्ज के बोझ में दबने के बाद श्रीलंका को इस बंदरगाह को मजबूरन चीन को 99 वर्ष की लीज पर देना पड़ा। ऐसा कई देशों में देखा जा रहा है कि देश चीन के कर्ज के बोझ में दबे जा रहे हैं। इस त्रासदी के चलते कई देशों ने चीन की इस परियोजना से हाथ खींचने शुरू कर दिए। मलेशिया ने चीन द्वारा प्रस्तावित योजना को घटाकर बहुत छोटा कर दिया है। दूसरे देश भी सक्रियता से ऐसा सोच रहे हैं। कई देशों में चीन का राजनीतिक दखल भी बढ़ चुका है। जिससे उन देशों की जनता त्रस्त है। उनमें पाकिस्तान एक ऐसा देश है। पाकिस्तान में सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनामिक कॉरिडोर इसी प्रकार की योजना का एक उदाहरण है। पाकिस्तान की सरकार ने भी कर्ज न चुका सकने की हालत में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं।

चीन का एकमात्र मकसद अपनी कंपनियों को व्यवसाय दिलाना, अपने कार्मिकों के लिए काम की व्यवस्था करना और दुनिया के मुल्कों को कर्ज में दबाकर उनसे न केवल अनुचित ब्याज वसूलना है, बल्कि पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाना है।

यही नहीं चीन की एक टेलीकॉम कंपनी हुआवे के भी किस्से काफी डरावने हैं। 5जी के लिए उपकरण और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के नाम पर विभिन्न देशों में जाल बिछाने का काम यह कंपनी कर रही है। इस कंपनी पर यह आरोप है कि वह 5जी के लिए संरचनात्मक ढांचा उपलब्ध कराने के नाम पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सूचनाओं पर अपना शिकंजा कसना चाहती हैं। सर्वविदित ही है कि चीन के कानूनों के आधार पर उसकी सभी कंपनियों को अनिवार्य रूप से सभी आंकड़े और सूचनाएं साझा करने की अनिवार्यता है। भारत सहित अधिकांश

चीन का एकमात्र मकसद अपनी कंपनियों को व्यवसाय दिलाना, अपने कार्मिकों के लिए काम की व्यवस्था करना और दुनिया के मुल्कों को कर्ज में दबाकर उनसे न केवल अनुचित ब्याज वसूलना है, बल्कि पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाना है।

मुल्कों में इस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन राजनीतिक दबाव अथवा झांसों के द्वारा यह कंपनी कई मुल्कों में ठेका प्राप्त करने में सफल हो चुकी है। भारत में हालांकि इसे ठेका तो नहीं मिला फिर भी ट्रायल के लिए इसे मौका जरूर मिल चुका है। कई टेलीकॉम कंपनियां हुआवे के पक्ष में अपनी राय रख रही है। लेकिन अमेरिका ने सामरिक चिंताओं के हवाले से इस कंपनी के विस्तार को रोकने का काम जरूर किया है।

यही नहीं चीन की कई कंपनियां दुनिया भर में चल रहे व्यवसायों का अधिग्रहण करने में संलग्न है। भारत में पेटीएम समेत कई पेमेंट कंपनियों और विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों का अधिग्रहण चीन ने किया है। यही नहीं भारत सरकार की स्टार्टअप योजना के तहत प्रारंभ किए गए स्टार्टअप व्यवसायों को भी चीनी निवेशकों की फंडिंग के माध्यम से कब्जाया जा रहा है।

चीनी वायरस ने बदल दिया है रुख

चीनी कंपनियों, चीनी वस्तुओं और चीन द्वारा प्रस्तावित बेल्ट रोड के प्रति दुनिया का पहले से रुख बदल ही रहा था। दुनिया को समझ आ रहा था कि चीन उनकी अर्थव्यवस्थाओं को तहस–नहस करने, उन्हें कर्ज के बोझ में दबाने, रोजगार को नष्ट करने, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के रास्ते डाटा (आंकड़ों) पर कब्जा जमाकर सामरिक दृष्टि से उन्हे कमजोर कर रहा है।

लेकिन पिछले लगभग दो माह में परिस्थितियां चीन के और अधिक विरूद्ध हो चुकी हैं। चीनी वायरस के कहर के कारण दुनिया भर में एक ओर मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हुई है, तो दूसरी ओर विभिन्न देशों की आपातकालीन परिस्थितियों के चलते चीन से मास्क, पीपीई किट्स और टेस्ट किट्स की मांग बढ़ गई है। इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने न केवल कीमतें बढ़ा दी हैं, बल्कि घटिया सामान निर्यात करना शुरू कर दिया। ऐसे में पहले से ही चीन से शुरू हुए वायरस से त्रस्त देशों का चीन के प्रति गुस्सा और अधिक बढ़ गया है और उन्होंने चीन से आये घटिया सामान को लौटा दिया है। इतना ही नहीं दुनियाभर के शेयर बाजारों में कीमतें घटने के बाद चीन द्वारा यूरोप और अन्य देशों में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाकर कंपनियों के अधिग्रहण के प्रयासों के मद्देनजर, अपने–अपने देशों में एफडीआई नियमों को बदल कर चीन के ऐसे कुत्सित प्रयासों को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत ने भी अपने एफडीआई कानूनों को बदलकर चीन सहित अपने पड़ोसी देशों से आने वाले निवेशकों को ऑटोमेटिक मार्ग से हटा दिया है। अब चीन से आने वाले निवेशकों को सरकार की अनुमति से ही आने दिया जाएगा।

दुनिया भर में चीन के प्रति गुस्से और उसके कुत्सित प्रयासों के खिलाफ बढ़ती जागृति के चलते भविष्य में चीन के दूसरे मुल्कों के साथ आर्थिक संबंध पूर्व जैसे नहीं रहेंगे। ऐसा लगता है कि चीन ने पिछले 20 सालों में भूमंडलीकरण का जो लाभ उठाया है उसके आगे का रास्ता सुगम रहने वाला नहीं। ❑❑

कोरोना के आगे है कामयाबी...

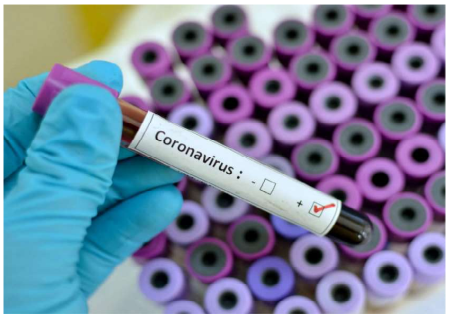

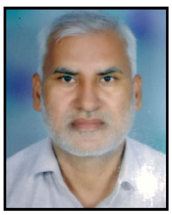

धीरे–धीरे यह धारणा घर करती जा रही है कि कोरोना लंबे समय तक मानव जीवन को हलकान fd , jgskA dksfoM& *19 का वायरस इंसानी जीवन और तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को धराशाई कर चुका है। अब सबका प्रयास है कि इस नामुराद बीमारी के बरक्स मजबूती से जीवन के साथ आजीविका के अवसरों का बचाया जाए। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने भारी भरकम आर्थिक पैकेज घोषित किया है। जिसमें पूरा जोर भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर है।*

– अनिल तिवारी

आत्मनिर्भर भारत की गूंज ऐसे समय में उठी है जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका कोरोना की मार से निराश है और यूरोप के ज्यादातर विकसित देश पूरी तरह हताश हैं। हर संकट अवसर लेकर आता है और देशवासियों में उम्मीद जगाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने इसी बात को अपना सूत्र वाक्य बनाया है। देश में पहला लॉकडाउन लगाते वक्त प्रधानमंत्री ने 'जान है तो जहान है' का नारा देकर आर्थिक गतिविधियों पर जिंदगी को वरीयता दी थी। लेकिन चौथे लॉकडाउन तक आते–आते जीवन और आर्थिक गतिविधियों को तराजू के संतुलित पलड़ों की तरह बताते हुए उन्होंने नारे में संशोधन करते हुए कहा 'जान भी जहान भी'। आत्मनिर्भर भारत का नया संकल्प कोरोना की विभीषिका से डटकर मुकाबला करने और देश के कदम नहीं रुकने देने का ऐलान है।

महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हमारी पूरी इकोनॉमी का 10 प्रतिशत हिस्सा है। इसका मकसद अर्थव्यवस्था में नई जान डालने और लॉकडाउन की मार झेल रहे कामगार कारोबारी जगत को राहत पहुंचाना है।

मालूम हो कि अमेरिका जापान स्वीडन और जर्मनी के बाद भारत ही है जिसने अपनी जीडीपी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक रकम कोरोना पैकेज के तौर पर खर्च करने का बजट रखा है। फ्रांस ने अपनी जीडीपी का 9.3 प्रतिशत, 7.3 प्रतिशत इटली, 5.7 प्रतिशत ब्रिटेन, 4 प्रतिशत चीन, 3.8 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया 2.2 प्रतिशत ही खर्च कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि यहां देश के 10 राज्यों में कोरोना के 90 प्रतिशत मामले हैं। इसलिए अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज सिर्फ कोरोना पैकेज होता तो आवंटन के मामले में इन 10 राज्यों को ही प्रमुखता मिलनी चाहिए थी। मगर ऐसा नहीं है इसीलिए कोरोना पैकेज के बजाए इसे कोरोना बजट कहना अधिक उपयुक्त लगता है। मौजूदा वक्त में चीन की विश्वसनीयता घटी है और महामारी के कारण अमेरिका के साथ–साथ पूरे यूरोप की स्थिति कमजोर हुई है। ऐसे में भारत के लिए एक अच्छा अवसर है। भारत में मेक इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर भारत का डंका पूरी दुनिया के बाजार में बजा सकता है।

महामारी के चलते विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक कार्य विभाग वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 0.9 प्रतिशत की दर से सिकुड़ने का अनुमान लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर फिंच रेटिंग संस्था के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था 3.9 प्रतिशत की दर से से खुलेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुमान से वैश्विक अर्थव्यवस्था 3 प्रतिशत की दर से शुरू करेगी और यह विगत 100 वर्षों में दूसरी सबसे बड़ी मंदी होगी। आईएमएफ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कम होकर 1.9 प्रतिशत हो जाएगी। परंतु वृद्धि दर सकारात्मक ही रहेगी जो भारत के लिए अन्य देशों की तुलना में एक बेहतर परिस्थिति है। नीति आयोग के एक अध्ययन के आधार पर भारतीय कृषि क्षेत्र की विकास दर कोरोना संक्रमित अर्थव्यवस्था में भी 3 प्रतिशत रहेगी जो पिछले वर्ष के 3.7 प्रतिशतसे बहुत कम नहीं है।

संकट को देखते हुए मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग के साथ ही इकोनॉमी के लिहाज से अहम दूसरे सेक्टरों को भी मजबूती से खड़ा करने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है इस बाबत सरकार पहले से ही कदम उठा रही है। कैश फ्लो बनाए रखने के लिए आरबीआई पिछले

3 महीनों में चार बार अर्थव्यवस्था को लिक्विडिटी इंजेक्शन लगा चुका है। पहले लॉकडाउन के 2 दिन बाद 27 मार्च को वित्तमंत्री ने भी 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इन सभी को अगर जोड़ दें तो 9.74 लाख करोड रुपए होते हैं।

आपूर्ति चेन को दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख 97 हजार करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। वित्तमंत्री ने लगातार पांच दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण कदमों की विस्तार से जानकारी दी। सरकार ने समाज के आखिरी मुकाम पर खड़े लोगों तक मदद पहुंचाने का दावा किया है। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने किसान प्रवासी मजदूर एमएसएमई कारपोरेट सेक्टर आज हर सभी के लिए जरूरी कदम उठाया है।

बड़े बाजार से किसानों की आय बढ़ाने का रोडमैप पेश करते हुए कृषि क्षेत्र में सुधार उत्पादन, गुणवत्ता, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर रहा। किसानों के लिए भारतीय बाजारों का दायरा बढ़ाने के साथ–साथ वैश्विक बाजार तक उनकी पहुंच बनाने और उत्पादों की ब्रांडिंग का ढांचा भी तैयार करने के लिए कदम उठाया गया है। सरकार ने इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या अनाज की कटाई के बाद उसकी बिक्री और भंडारण को लेकर है। इसके लिए सरकार ने पारदर्शी तरीके से प्रसंस्करण एग्रीगेटर और बड़े खुदरा विक्रेताओं की ओर निर्यातकों की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए कार्यक्रम बनाने का ऐलान किया है। इस काम में एग्री स्टार्टअप से तकनीक और कंपनियां मददगार होंगी। इससे उन्हें आकर्षक मूल्य पर उपज बेचने का विकल्प मिलेगा।

'एक देश–एक राशन कार्ड' योजना अगस्त 2020 तक लागू हो जाएगी। इससे देश के किसी भी हिस्से के डिपो से राशन लिया जा सकता है। मार्च 2021 तक 100 प्रतिशत राष्ट्रीय पोटेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी। इससे प्रवासी मजदूरों को देश में कहीं भी राशन की दुकान से राशन लेने की सुविधा प्राप्त होगी।

प्रवासी मजदूरों को उनके निवास स्थान के निकट काम दिलाने की गरज से मनरेगा का बजट बढ़ा दिया गया है। इस बजट में अतिरिक्त 40 हजार करोड रुपए का आवंटन किया गया है। स्वास्थ्य बजट में वृद्धि किए जाने के साथ–साथ मजदूरों को मुफ्त भोजन देने तथा उन्हें सरकारी खर्चे से उनके निवास स्थान पर पहुंचाने की भी व्यवस्था केंद्र की सरकार की ओर से की जा रही है। कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म करने की घोषणा हुई है।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग देश की अर्थव्यवस्था के विकास में एक अहम भूमिका अदा करता है। एमएसएमई क्षेत्र की देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन में 45 प्रतिशत और निर्यात में 48 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। कृषि क्षेत्र के बाद एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार के सबसे अधिक अवसर निर्मित होते हैं। 73वें राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के अनुसार देश में एमएसएमई क्षेत्र में 6.34 करोड़ इकाइयां कार्यरत थी, जिनके माध्यम से एक 11.1 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था के लिए विकास का इंजन कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही कारण है कि सरकार ने इस क्षेत्र को विशेष रूप से आर्थिक पैकेज के तहत अधिकतम तरलता प्रदान करने का एक तार्किक निर्णय लिया है क्योंकि देश में लगभग 2 माह के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद जब किसी औद्योगिक इकाई को पुनः चालू किया जाएगा तो सबसे पहले उसे तरल पूंजी की आवश्यकता होगी। पर्याप्त पूंजी हाथ में आने के बाद ही कोई भी औद्योगिक इकाई आर्थिक गतिविधियों से संबंधित अन्य कार्य प्रारंभ कर पाएंगी।

इसके साथ ही कोरोना की लड़ाई में स्वास्थ्य सेवाओं को भी और मजबूती देने की कोशिश की गई है। पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपए जारी करके उस आलोचना का भी जवाब दिया गया है। जिसमें कहा जा रहा था कि इस फंड का पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा है। इसमें से 2000 करोड रुपए वेंटिलेटर पर और 1000 करोड़ रुपये प्रवासी मजदूरों पर खर्च होंगे। दोनों तात्कालिक और फौरी जरूरत है।

यकीनन आगे का रास्ता कठिन है। मगर आत्मनिर्भरता का नारा देकर प्रधानमंत्री ने चुनौतियों के बीच उम्मीद को नई रोशनी देने की कोशिश की है। यह भी गौर करने वाली बात है कि आज जिन्हें हम विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था में कहते हैं, वह सब कुछ ना कुछ अंशों में अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर है। ऐसे में अगर हमारा देश विकास की नई स्वदेशी जमीन तैयार कर पाता है तो यह न केवल हमारी मुश्किलें दूर करेगा बल्कि दुनिया के लिए भी एक नई मिसाल का काम करेगा।

प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लक्ष्य साधक फोर–एल यानी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ से जुड़ी बारीकियों पर जोर देते हुए इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड जैसे पांच सीढ़ियों को मजबूती देने का आह्वान किया है। इससे यह साफ है कि इन 9 शब्दों की सीढ़ियों के सहारे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। जरूरत है स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत होकर इस पर आगे बढ़ने की। ❑❑

कोरोना के कहर में कैसे दें चीन को मात

चीन की तुलना में हमारी तीन ताकत है। पहली यह कि हमारी जनसंख्या की औसत आयु 28 वर्ष है, जबकि चीन की जनसंख्या की 38 वर्ष। कोरोना वायरस युवाओं को कम प्रभावित करता है इसलिए हमारे यहां कोरोना का संकट कम होना चाहिए। दूसरी, हमारे देश का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है जबकि चीन का 7 डिग्री सेल्सियस। हमारा देश गर्म होने के कारण कोरोना का प्रभाव कम होना चाहिए। तीसरी ताकत यह है कि हमारी महारत सेवा क्षेत्र में है, जैसे– साफ्टवेयर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इत्यादि में। यह क्षेत्र कोरोना से कम प्रभावित होता है, क्योंकि इस क्षेत्र की तमाम सेवाओं को घर से प्रदान किया जा सकता है। तुलना में चीन की महारत मैन्यूफैक्चरिंग में है, जहां पर श्रमिकों का एक स्थान पर आना और मिलकर कार्य करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हमारे लिए कोरोना के संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को चालू रखना ज्यादा संभव है।

इन तीनों ताकतों के बावजूद आज चीन में नये कोरोना के केस लगभग शून्य प्राय हो गये हैं और कुल 82 हजार केस आज तक हुए हैं। तुलना में अपने देश में प्रतिदिन लगभग 4 हजार केस बन रहे हैं और लगभग 90 हजार आज लेख लिखते समय हो चुके हैं। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में यह संख्या कई गुणा अधिक हो सकती है। यानि अपनी तीनों ताकतों के बावजूद हमारी स्थिति चीन की तुलना में ज्यादा गड़बड़ है। इसका मुख्य कारण यह है कि चीन ने लाकडाउन को सख्ती से लागू किया। उनका प्रशासन कुशल था। तुलना में अपने देश में ताबलीकी जमात के कारण, प्रवासी श्रमिकों को लाकडाउन में राहत न देने के कारण, शराब की बिक्री खोलने के कारण और धारावी जैसी झुग्गी बस्तियों के कारण हम करोना के फैलाव को रोकने में पूरी तरह असफल रहे हैं। हमारा प्रशासन फेल है। हमारी यह असफलता आज भी जारी है।

सरकार को वित्तीय घाटा बढ़ाकर यानि ऋण लेकर इस संकट से उबरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सरकार यदि विश्व बाजार से ऋण लेती है तो उस ऋण का एक हिस्सा चीन से आएगा और हम पुनः किसी न किसी रूप में चीन के दबाव में आयेंगे।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

चीन ने अपने मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को पुनः चालू कर लिया है। आज विश्व में संभवतः चीन अकेला बड़ा देश है कि जो कि माल का पुरजोर उत्पादन कर विश्व को सप्लाई कर सकता है। इसलिए यदि दुनिया के किसी भी देश को कोई माल की जरूरत पड़े तो आज उसे मजबूरन चीन से ही उसे खरीदना होगा।

इस समय चीन के विरुद्ध अमरीका के राष्ट्रपति ट्रम्प शोर मचा रहे हैं। वे पूरे विश्व को चीन के विरोध में लामबंद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह शोर टिकेगा नहीं। ट्रम्प के शोर मचाने के पीछे अमरीका की गड़बड़ाती अर्थव्यवस्था दिखती है। अमरीकी सरकार भारी मात्रा में विश्व बाजार से ऋण ले रही है और इस ऋण का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था को बनाये रखने के लिए कर रही है।

विश्व बाजार में यह ऋण बड़ी मात्रा में चीन द्वारा ही सप्लाई किया जा रहा है। अमरीकी सरकार द्वारा लिए गये ऋण में 15 प्रतिशत सीधे चीन द्वारा उपलब्ध कराया गया है। दूसरे देशों द्वारा भी उपलब्ध कराए गये ऋण में चीन का हिस्सा दिखता है। जैसे चीन ने इंग्लैंड के बैंकों में रकम जमा कराई और इंग्लैंड के बैंकों ने उस रकम से अमरीकी सरकार द्वारा जीरो ट्रेजरी बांड खरीदे। इसलिए अमरीका आर्थिक दृष्टि से दबा हुआ है और इस दबाव के कारण राष्ट्रपति ट्रम्प चीन के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। बताते चलें कि लगभग चार वर्ष पूर्व अमरीका की खुफ़िया सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा था कि अमरीका की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा चीन की मुद्रा रेनमिन्बी से है। यानि सामरिक दृष्टि से अमरीका चीन से आर्थिक दृष्टि से दबता जा रहा है और इस कारण अमरीका की संप्रभुता ही संकट में आ रही है। अतः ट्रम्प का शोर चीन के कारनामों के कारण कम और अपने कारनामों के कारण ज्यादा हैं। इसलिए यह शोर नहीं टिकेगा।

चीन ने अपने मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को पुनः चालू कर लिया है। आज विश्व में संभवतः चीन अकेला बड़ा देश है कि जो कि माल का पुरजोर उत्पादन कर विश्व को सप्लाई कर सकता है। इसलिए यदि दुनिया के किसी भी देश को कोई माल की जरूरत पड़े तो आज उसे मजबूरन चीन से ही उसे खरीदना होगा।

ट्रम्प के शोर के न टिकने का दूसरा कारण यह है कि बड़ी कंपनियों के लिए चीन से मैत्री लाभप्रद है। बड़ी कंपनियाँ एक देश से माल बनाकर दूसरे देश में सप्लाई करती हैं। उनके लिए विश्व अर्थव्यवस्था का खुला रहना लाभप्रद होता है। इसलिए कुछ समय बाद अध्ययन प्रकाशित होने लगेंगे कि कोरोना का संकट आकस्मिक था और यह जरूरी नहीं कि ऐसा संकट दुबारा आये। ध्यान दिला दें कि 2013 में केदारनाथ में भारी तबाही मची थी। लेकिन जल विद्युत् कंपनियों ने प्रसार किया कि यह एक आकस्मिक घटना थी और आज त्रासदी को अनदेखा करके जल विद्युत् परियोजनाओं के निर्माण को भारी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी प्रकार कोरोना को भी हम शीघ्र भूल जायेंगे। इन सब बातों को देखते हुए मेरा अनुमान है कि कोरोना संकट के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में चीन का दर्जा बढ़ेगा, घटेगा नहीं।

फिर भी भारत के लिए अवसर है। हमने मैन्यूफैक्चरिंग का एक बड़ा अवसर पहले ही गँवा दिया है। मार्च में लॉकडाउन करते समय यदि सरकार फैक्ट्रियों को छूट देती कि वे अपनी सरहद में ही श्रमिकों के रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराएँ और अपनी फैक्ट्री चालू रखें तो आर्थिक संकट नहीं गहराता और हम उत्पादन जारी रखते और माल बनाकर निर्यात करते रह सकते थे। अपने मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों को जारी रख सकते थे। यह चूक हो ही गयी है तो भी आज यह व्यवस्था की जा सकती है। जितने भी औद्योगिक संसाधन हैं उनसे कहा जा सकता है कि वे अपने श्रमिकों के रहने खाने की व्यवस्था अपने यहाँ करे और उत्पादन शुरू करें।

दूसरी बात यह कि सरकार को वित्तीय घाटा बढ़ाकर यानि ऋण लेकर इस संकट से उबरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सरकार यदि विश्व बाजार से ऋण लेती है तो उस ऋण का एक हिस्सा चीन से आएगा और हम पुनः किसी न किसी रूप में चीन के दबाव में आयेंगे। उत्तम तो यह होगा कि पेट्रोल पर वर्तमान में 25 रूपये प्रति लीटर का जो टैक्स केन्द्र सरकार द्वारा वसूल किया जा रहा है उसे बढ़ाकर सीधे 100 रुपया कर दें और इस रास्ते लगभग 10 लाख करोड़ रूपये की वार्षिक आय हो सकती है जिसका उपयोग हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कर सकते हैं। ऐसा करने से पेट्रोल के ऊँचे दामों का विशेष दुष्प्रभाव उन सम्भ्रांत वर्ग पर पड़ेगा जो कि बाहर से लाये हुए माल को अथवा उर्जा सघन माल की खपत करते हैं। आम आदमी इससे अछूता रहेगा और भारत सरकार को विश्व बाजार के सामने ऋण के लिए अपनी झोली नहीं फैलानी पड़ेगी। यदि हम ये दो कार्य कर दें तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू कर सकते हैं और चीन का सामना कर सकते हैं। ❑❑

आत्मनिर्भर मॉडल ही महामारी के मकड़जाल से निकलने का महामंत्र

आज का ज्वलंत मुद्दा है कि कोरोना महामारी से जर्जर हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर कैसे लाया जाए? वर्तमान प्रचलित उपचार पद्धति कहती है कि कोरोना की दवा किसी के पास नहीं, परंतु भारत की हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवा मांगने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने गुहार लगाई। आयुर्वेदिक काढ़े व जड़ी–बूटियों आदि की मांग भी बढ़ रही है। दूसरी ओर वैश्विक सामाजिक–आर्थिक संरचनाएं भी इस समय निरर्थक सिद्ध हो रही हैं और भारत जैसे देश का मुंह ताक रही हैं। भारतीय मेधा ने जिस स्वदेशी प्रतिमान को कभी इस देश में खड़ा किया, कोरोना महामारी से लड़खड़ाती दुनिया उसे बड़ी आशा से निहार रही है। इसलिए जरूरी हो गया है कि इसे एक विमर्श का मुद्दा बनाया जाए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघचालक मोहनराव भागवत ने बड़े ही सटीक व सम–सामयिक ढंग से इस ओर कई संकेत किए हैं, जिन्हें हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने इस समय राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण में दो प्रकार के विषयों को छुआ है, तात्कालिक व दीर्घकालीन। तात्कालिक कामों में पहले उल्लेख किया शहरों से गांव लौटते हुए मजदूरों का। क्या हम गांव में ही उन्हें रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध करा सकते हैं? ऐसे में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, एपीजे अब्दुल कलाम के 'पूरा' (प्रोविजन ऑफ अरबन एमिनीटिज इन रूरल एरियाज) से लेकर नानाजी देशमुख के समग्र विकास तक के उदाहरणों के संदर्भ ताजा हो गए हैं। इस टिप्पणी के पीछे एक पूरी संघ दृष्टि है। ग्राम विकास के कार्यों में लगे हजारों स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं का परिश्रम और प्रयोगधर्मिता इसकी अधोरचना है। ऐसे में इन लाखों कामगारों को गांव में ही रोजगार मुहैया करवा कर एक बड़ी समस्या का समाधान खोजा जा सकता है।

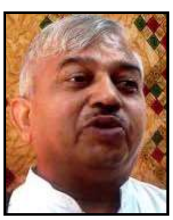

बाजारी ताकतों ने आर्थिक विकास का जो आदर्श बनाया, वह कोरोना काल में ढह गया। उसकी जगह आत्मनिर्भर मॉडल ही इस महामारी के मकड़जाल से निकलने का सही मंत्र दिखता है।

– कश्मीरी लाल

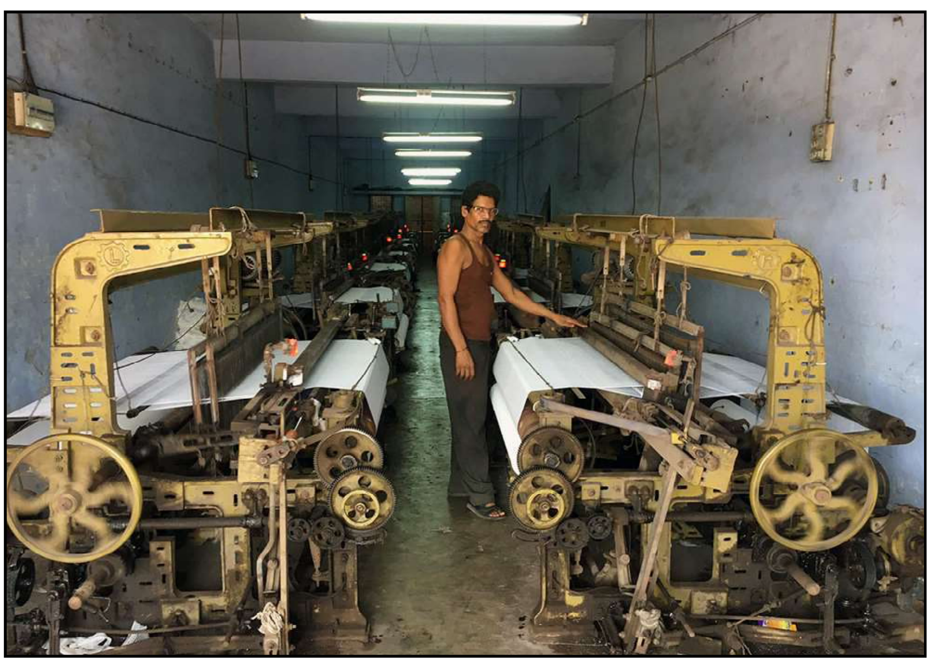

दूसरा तात्कालिक काम है, गांव से दोबारा शहर जाने वालों के लिए काम– धंधे ढूंढना। चूंकि अधिकांश उद्योग बंद हैं, वैश्विक मांग में भी भारी कमी हो गई है। ऐसे में दोबारा उन्हें खपाने व रोजगार दिलाने की कितनी क्षमता यहां है, इसे देखना पड़ेगा। वे उद्योग भी घाटे में चल रहे होंगे, लिहाजा आपसी सद्भाव व समझदारी से दोनों को कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। यानि पुनर्निर्माण में मालिक–मजदूर का समन्वय आवश्यक है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जिस मालिक–मजदूर के आपसी सौहार्द की बात करते थे, यह उस विचार की ओर संकेत है।

तीसरा बड़ा दीर्घकालीन विचार विकास का वैकल्पिक मॉडल है। 'स्वावलंबन' शब्द और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की देश भर के सरपंचों से हुई बातचीत का संदर्भ दिया। यह संदर्भ एक संकेत दे रहा है कि किस प्रकार इस समय शासन 'विकेंद्रित' आर्थिक संरचना के लिए तैयारी कर रहा है। कोरोना महामारी आज एलपीजी मॉडल (लिबरेलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन व ग्लोबलाइजेशन) के खोखलेपन को उजागर कर रही है। यह बाजार की ताकतों का बनाया हुआ प्रतिमान था, जो इस समय दम तोड़ रहा है। उसकी जगह ग्राम स्वराज्य व जिलों पर आधारित अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर मॉडल इस महामारी रूपी आपत्तिकाल का मंत्र है। इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 'स्व' शब्द पर जोर दिया और स्वदेश के विकास मॉडल को विकसित करने का उल्लेख किया। चौथी बात कही कि आधुनिक विज्ञान का प्रयोग हो, परंतु अपनी परंपरा का भी ध्यान रखना चाहिए।

विदेशी विकास मॉडल की खामियांः आज विदेशी विकास मॉडल की खामियां जगजाहिर हैं। यह अत्यधिक उर्जाभक्षी, रोजगारविहीन व पर्यावरण भक्षक है। ऐसे मॉडल की

इस समय दुनिया के अधिकांश देश चीन से त्रस्त हैं, वहां से कंपनियां आज अन्य देशों में जाने को आतुर हैं। ऐसे में भारत को अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी।

गहन विवेचना राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने पुस्तिका 'द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड थर्ड वे' में की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व गांधीजी ने भी हिंद स्वराज में इस पश्चिमी मॉडल की धज्जियां उड़ाई हैं। विदेशों में भी इस विकास मॉडल की चीर–फाड़ हुई है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के फैलाव का मुख्य कारण अति–शहरीकरण, वैश्वीकरण तथा अत्यधिक संपर्क है। जहां–जहां यह पश्चिम मॉडल प्रसिद्ध हुई, वहां भी इसके दुष्परिणामों के कारण इसका विरोध हो रहा है। इसलिए कोई विकेंद्रित व आत्मनिर्भर मॉडल ही इन बीमारियों से बचा सकता है, ऐसी चहुंओर चर्चा है।

एक अहम प्रश्न यह है कि इस वैकल्पिक स्वदेशी संरचना को कौन लागू करेगा। दरअसल यह तीन स्तरों पर हो सकता है। शासन, प्रशासन एवं समाज द्वारा। शासन प्रमुख रुचि दिखा रहे हैं। सरपंचों के साथ अपनी वार्ता में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर मॉडल के चार पायदान बताए– गांव, जिला, प्रांत व देश। जहां तक प्रशासन का सवाल है तो कायदे से वह उसी को करने को प्रतिबद्ध है जिसे शासन कहेगा या उनसे करवा लेगा। अतः तीसरा काम समाज को करना होता है और वह काम सतत व नियोजित जनजागरण से होता है।

स्वदेशी बने मूलमंत्रः जीवन में स्वदेशी अपनाने पर पूरा जोर देना होगा और विदेशी से दूरी बनाए रखना होगा। जीवन के लिए जो आवश्यक है, उसे यहां तैयार करना होगा और उसकी गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आज नई चुनौती चीन से अत्यधिक आयात की है। प्रति वर्ष 54 से 64 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हमें चीन से हो रहा है। जिस प्रकार कोरोना महामारी के बाद भी दुनिया को घेरने में चीन संलग्न है, वह एक खतरे की घंटी है। इस कारक को समझना होगा। इस समय दुनिया के अधिकांश देश चीन से त्रस्त हैं, वहां से कंपनियां आज अन्य देशों में जाने को आतुर हैं। ऐसे में भारत को अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी। साथ ही स्वदेशी ज्ञान व विज्ञान संवर्धन भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जैविक कृषि, योग, आयुर्वेद आदि को बढ़ावा देना होगा।❑❑

(लेखक संगठक, स्वदेशी जागरण मंच)

आर्थिक नीतियों की समीक्षा का समय

कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के लगभग सभी देश इसके लिए चीन को आरोपित कर रहे हैं। दाल में कुछ काला है। आखिर चीन ने अपने देश में कोरोना को इतना जल्दी कैसे नियंत्रण कर लिया और इस वायरस को वुहान से बाहर भी नहीं फैलने दिया। जबकि बाकी विश्व में मृतकों की संख्या तीन लाख के आंकड़े को पार कर गई है। चीन कोरोना वायरस संबंधी कोई भी सूचना सांझा नहीं कर रहा है, केवल माल बेच रहा है, व्यापार बढ़ा रहा है।

भारत अपनी संकल्प शक्ति व सरकार द्वारा समय पर लिए गए लॉकडाउन के निर्णयों से हम बीमारी के ग्राफ को झुकाने में सफल हुए हैं। हमें लॉकडाउन के कारण आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ी है। लेकिन आज एक सवाल बड़ा प्रासंगिक हो जाता है कि क्या वैश्वीकरण और निजीकरण के बलबूते कोरोना की लड़ाई लड़ी और जीती जा सकती थी?

जिस एयर इंडिया को घाटे का सौदा बताकर बेचने के प्रयास हो रहे थे, लेकिन कोई भी खरीददार नहीं मिल रहा था। याद कीजिए विदेशों से भारतीयों को निकालकर यही 'एयर इंडिया' ही लेकर आई थी। कोरोना के खिलाफ युद्ध में एक सैनिक की तरह लड़ रहे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस, सफाई कर्मचारी क्या किसी निजी कंपनी के हैं?

सरकार अपने संसाधनों के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। यह एयर–इंडिया, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे, क्या इनके बिना कोरोना से लड़ा जा सकता था? अकेले रेलवे ने ही एक लाख से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था अपनी रेलों में कर दी है। माल गाड़ियों के माध्यम से देश में कहीं भी खाद्यान्न व दूसरी जरूरत की चीजों की कमी नहीं होने दी।

जो संस्थाएं, नीति–निर्माता या व्यक्ति हर समस्या का समाधान निजीकरण में ढूंढते थे, वे जरा स्थिति का अनुमान लगाएं कि अगर यह सभी सेवाएं निजी हाथों में होती तो क्या होता? क्या हम तब इतनी सफलता और कुशलता से कोरोना से लड़ सकते थे?

स्वावलंबन के लिए स्वदेशी और ग्राम आधारित रोजगारपरक उद्योग ही आशा की किरण है। आशा है कि आगामी नीतियाँ इसी दिशा में बनेगी ताकि भारत अपनी बुनियादी समस्याओं से निबट सके तथा विश्व गुरु का अपना स्थान पुनः प्राप्त कर सके।

– **दुलीचन्द कालीरमन**

वैश्वीकरण का भी यही हाल है। सभी को पता है कि इस सारे संकट के पीछे चीन है। लेकिन कोई भी देश खुलकर कुछ भी ज्यादा नहीं बोल पा रहा। क्योंकि टेस्टिंग किट भी चीन से चाहिए, वेंटिलेटर भी वही देगा और डाक्टरों के लिए पर्सनल प्रोटक्शन इक्विपमेंट चीन से ही आएंगे। यह स्थिति है कि कोई मारे भी और रोने भी नहीं देता।

भारत में कोरोना का कहर नियंत्रण में रहने का एक अन्य कारण हमारा खानपान है। जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। अब तो आयुष मंत्रालय ने देशी काढ़े व अन्य रसोई में प्रयोग होने वाली हल्दी, इलायची, काली–मिर्च, दालचीनी की उपयोगिता पर अपनी मुहर लगा दी है। भारतीय मौसम के हिसाब से हमें अपनी देशी खानपान व जीवन शैली को अपनाए रखना होगा।

कोरोना के बाद की विश्व–व्यवस्था बिल्कुल अलग होगी। जिस प्रकार "विश्व स्वास्थ्य संगठन" जैसे संगठनों पर उंगलियां उठ रही हैं। "विश्व व्यापार संगठन" पहले ही मृत प्राय हो चुका है। हर देश की प्राथमिकता स्वावलंबन की दिशा में होगी। वैश्विक आर्थिक मंदी तो आना लाजमी है। चीन दुनिया की नजरों में विलेन बन चुका है। भारत की अपनी आबादी ही 130 करोड़ है। हमारे यहां मांग में कमी नहीं आएगी बल्कि यहां स्वयं के उद्योग लगाने के लिए सरकारों को प्रोत्साहन देने के अपने प्रयासों को और भी तेज करना होगा ताकि वे स्वावलंबी हो और भारत की बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो सके। विकसित देशों की जो बड़ी–बड़ी कंपनियां चीन में अपने कारखाने चला रही थी, वे भारत का रुख करेंगी। ऐसे में हमें अपनी प्राथमिकताएं और शर्तें अपनी अग्रिम योजनाओं के अनुसार तय करनी होंगी।

एक कहावत हैं कि संकट काल में ही किसी भी व्यक्ति की सर्वोच्च क्षमता का पता चलता है। भारतीय उद्योग जगत ने इतने कम वक्त में वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट, पर्सनल प्रोटक्शन इक्विपमेंट बना कर यह साबित कर दिया है। आर्थिक मंदी के दौर में सरकार को आर्थिक मदद देने के लिए भारतीय उद्यमी भी पीछे नहीं रहे। हम रात–दिन जिन विदेशी ब्रांड को धारण करके आधुनिक होने का गर्व करते हैं, वे विदेशी कंपनियां इस लड़ाई में कहीं नहीं दिखाई दी।

अब सरकारों तथा आम नागरिकों की यह जिम्मेदारी है कि वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना काल से सबक लेकर अपनी प्राथमिकताएं तय करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पंचायतों के सरपंचों के साथ अपने संबोधन में यह कहा था कि यह समय स्वावलंबन की सीख दे रहा है। स्वावलंबन के लिए स्वदेशी और ग्राम आधारित रोजगारपरक उद्योग ही आशा की किरण है। आशा है कि आगामी नीतियाँ इसी दिशा में बनेगी ताकि भारत अपनी बुनियादी समस्याओं से निबट सके तथा विश्व गुरु का अपना स्थान पुनः प्राप्त कर सके। ❑❑

कोरोना से ध्यान भटकाने में लगा चीन

कोरोना को लेकर वैश्विक दबाव में आया चीन मुद्दे को भटकाने के लिए भारत के खिलाफ सिक्किम में सीमा पर तनाव उत्पन्न कर रहा है। चीनी सैनिकों ने बगैर किसी उकसावे के भारतीय सैनिकों से हाथापाई की। हालांकि भारत ने इसका सख्ती से जवाब दिया। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना से मुकाबले का रास्ता खोज रही है। चीन की हरकत साबित करती है कि वह विश्व में अलग–थलग पड़ गया है।

चीन ने सिक्किम में उकसावे की कार्रवाई कर भारत के साथ जबरन तनाव उत्पन्न करने की कोशिश की है। चीन की मंशा भारत के खिलाफ कार्रवाई के साथ सीमा विवाद को भड़काकर अपने खिलाफ विश्व में बढ़ती नाराजगी से ध्यान भटकाना है। कोरोना से मुकाबला करने के लिए ताइवान के भारत को स्वास्थ्य संबंधी उपकरण देने से भी चीन भड़का हुआ है। मालूम हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में शिरकत के लिए ताइवान भारत से समर्थन की उम्मीद कर रहा है। इसके विपरीत चीन जबरदस्ती ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। चीन पूर्व में भी ताइवान के मुद्दे को घरेलू मामले की संज्ञा देता रहा है।

चीन के भारत से भड़कने के कारणों में भारत की नई एफडीआई पॉलिसी और पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा भी है। भारत ने समीपवर्ती देशों से सीधे एफडीआई पर पाबंदी लगा दी है। पिछले दिनों ही चीन ने एचडीएफसी में भारी निवेश किया था। कोरोना संक्रमण के बाद चीन में कार्यरत करीब 3000 विदेशी कंपनियां अपना कामकाज समेटकर दूसरे देशों में निवेश करना चाहती है। भारत ने इन कंपनियों को अपने यहां बुलाने के लिए कई तरह के सुगम निवेश की पेशकश की है। इससे चीन बौखलाया हुआ है। चीन की भारत के प्रति वैमनस्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों ब्रह्मपुत्र नदी में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से मरे सुअरों को बहाया गया था। इससे असम सहित पूर्वी राज्यों में अब तक 13000 सुअरों की मौत हो चुकी है। दो साल पहले भी डोकलाम में चीन ने इसी तरह की नापाक कोशिशें की थी। जिसका भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब चीन ने लद्दाख और सिक्किम के बीच भारतीय सैनिकों पर उसके ईलाके में जाने और चीन के सैनिकों को गश्त से रोकने की कोशिश का आरोप लगाया है। ❑❑

कोरोना से लड़ेंगें भी और जीतेंगे भी

कोई भी लड़ाई जीतने के लिए हथियारों से ज्यादा रणनीति कारगर होती है। आज हम जिस संप्रभु राष्ट्र के नागरिक हैं, उसकी आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और असहयोग की रणनीति को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल किया था। नहीं तो सामरिक और आर्थिक ताकत के बल पर देश को शायद आजादी न मिली होती। यह बात मैं वैश्विक महामारी कोरोना के संदर्भ में आज कह रहा हूं। जिस तरह से पूरी दुनिया आज इस वायरस के संक्रमण की चपेट में आती जा रही है। लोगों को इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका भी त्राहि–त्राहि कर रहा है। वहां के लोगों के सामने रोजी–रोजगार का संकट खड़ा हो गया है और खाने के लाले पड़ गए हैं। मीडिया रिपोर्टों पर गौर करें तो अमेरिका में फूड बैंक के सामने लंबी कतारें लग रही है और धीरे–धीरे आवश्यक वस्तुओं की कमी पड़ने लगी है। आज जब हम यह रिपोर्ट लिखने बैठे हैं पूरी दुनिया में लगभग 50 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 3 लाख से अधिक मौतें हो चुकी है। इनमें सर्वाधिक मौतें अमेरिका में हुई है। भारत में भी संक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 92000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 3000 तक पहुंच चुकी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टैड्रास एडहेनाम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि दुनिया के अधिकांश आबादी के संक्रमित होने का खतरा बरकरार है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी यूरोप में फैलाव की रफ्तार भले ही स्थिर हो, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उन्होंने भारत को भी चेताया है कि वह लॉक डाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति आगे चलकर नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यह सच है कि भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं है। अगर महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्यों को छोड़ दें तो अन्य राज्यों में संक्रमण की रफ्तार धीमी है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या पिछले एक महीने में हम कोरोना को पराजित करने में या कमजोर करने में कामयाब हो चुके हैं। मुझे लगता है नहीं। मेरा मानना है कि भारत का प्रत्येक नागरिक और हमारी सरकार मिलकर कोरोना के विरुद्ध रणनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं।

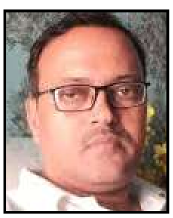

कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में हम अवश्य जीतेंगे। संसाधनों के अभाव के बावजूद जीतेंगे। यह जीत 130 करोड़ भारतवासियों के आत्मबल की जीत होगी। धैर्य की जीत होगी। परोपकार की भावना की जीत होगी।

– डॉ. निरंजन सिंह

यह सच है कि हमारे पास पर्याप्त चिकित्सकीय संसाधन नहीं है और नहीं हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं कि लंबे समय तक इस संकट के खिलाफ संघर्ष कर सकें। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनैतिक और रणनीतिक कौशल के बदौलत हम अभी तक की लड़ाई में कामयाब रहे हैं। देश के अंदर राजनीतिक और वैचारिक तौर पर दिवालिया हो चुके कुछ लोग और संगठन भले ही मोदी के ताली और थाली बजाने के संदेश का मजाक उड़ायें, किंतु पूरी दुनिया उनकी रणनीतिक कुशलता की तारीफ कर रही है। इसे राजनीतिक कुशलता ही कहेंगे की नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश की 130 करोड़ से अधिक की आबादी

बुनियादी जरूरतों का भारी अभाव झेलते हुए भी संकट की इस घड़ी में धैर्य और संयम का परिचय दे रही है। हम जॉन्स हापकिंस विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर और दुनिया के जाने–माने अर्थशास्त्री स्टीव हैंकी के उन विचारों से सहमत नहीं है कि कि नरेंद्र मोदी लॉक डाउन के लिए पहले से तैयार नहीं थे और उन्होंने संक्रमण से निपटने के लिए जरूरी उपकरण और आर्थिक संसाधन नहीं जुटाए। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि भारत के 81 फ़ीसदी आबादी असंगठित क्षेत्रों में काम करती है जिसके हितों के बारे में लॉक डाउन करने से पहले मोदी ने नहीं सोचा। अर्थशास्त्री स्टीव संपूर्ण नहीं बल्कि स्मार्ट लॉक डाउन की वकालत करते हैं और दक्षिण कोरिया, स्वीडन और हांगकांग जैसे देशों से भारत की तुलना करते हैं जो कि कहीं से भी समीचीन नहीं है। यह सच है कि भारत के पास इतनी बड़ी आबादी को चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी संसाधन नहीं है आंकड़ों पर अगर गौर करें तो यहां 1000 लोगों पर 0.7 बेड है जबकि इतने ही लोगों पर 0.08 डॉक्टर उपलब्ध है। सरकार ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई के लिए देश के लगभग 600 अस्पतालों में 18 लाख के लगभग बेड उपलब्ध है जो अभी तक के संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए पर्याप्त कहे जा सकते हैं। प्रश्न यह है कि आज अगर देश में पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो क्या इसके लिए हम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या पिछले 50 वर्षों तक सत्ता में रही पूर्व की सरकारें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

कांग्रेस जैसी अन्य विपक्षी पार्टियां भी और कांग्रेस शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री भी अब केंद्र पर इस बात के लिए निशाना साधने लगे हैं कि लॉक डाउन से पहले केंद्र ने जरूरी तैयारियां नहीं की। पर मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर किस तरह की तैयारियों की बात कर रहे हैं। अगर पूर्व की रणनीति नहीं होती तो लॉक डाउन शुरू होने के साथ ही देश के 80 करोड़ लोगों के लिए युद्ध स्तर पर राशन वितरण का कार्य शुरू होता। जनधन खातों में 3 महीने तक पैसे डालने से लेकर वृद्ध, विधवा और विकलांगों के लिए पेंशन की अतिरिक्त किस्त जैसी तमाम सुविधाएं केंद्र की ओर से उपलब्ध कराई जा सकती थी। वित्तमंत्री द्वारा 15,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज से लेकर रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट की दरों में लगातार कटौती, किसानों और व्यापारियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान। क्या यह सब पूर्व की रणनीति का हिस्सा नहीं है?

भारत के बारे में जानकारी देने वाले स्टीव जैसे अर्थशास्त्री को भारत की जमीनी हकीकत का अनुभव नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि अगर लॉक डाउन की घोषणा अचानक करने के बजाए समय देकर की जाती तो पूरे देश में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती। सिर्फ दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में ही 42 लाख से अधिक अप्रवासी मजदूर काम करते हैं, जिन्हें घरों तक पहुंचने में एक सप्ताह से अधिक समय लगता। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की आपाधापी में देश की पूरी परिवहन व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। वहीं जरूरी सामान जुटाने की भी जनता में होड़ लग जाती जिससे कानून और व्यवस्था की नई समस्या खड़ी हो सकती थी। हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि पिछले एक महीने के लॉक डाउन में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को विशेषकर विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, किंतु इस देश को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बाहर निकालने के लिए ऐसी कुर्बानी देने के अलावा देश के आम नागरिकों के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था और नहीं सरकार के सामने इससे कोई बेहतर रणनीति हो सकती थी।

कोरोना के खिलाफ लड़ाई कोई व्यक्ति विशेष या केंद्र सरकार की लड़ाई नहीं है। यह संपूर्ण मानवता को बचाने के लिए संपूर्ण मानव जाति की ओर से लड़ी जाने वाली लड़ाई है। अमेरिका और यूरोप के सक्षम देश कोरोना के विरुद्ध राष्ट्र विशेष की लड़ाई मानकर लड़ रहे हैं। जब संपूर्ण मानवता खतरे में है तब अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली अनुग्रह राशि पर रोक लगा दी है, वहीं दूसरे देशों के नागरिकों के बसने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। संकट की इस घड़ी में सर्वाधिक डरा हुआ अगर कोई राष्ट्र दिख रहा है तो वह अमेरिका है और उसका दुर्भाग्य यह है कि कोरोना संकट से सर्वाधिक प्रभावित भी वही है। दुनिया के उपभोक्ता बाजार पर कब्जा करके बैठा हुआ चीन, जो कोरोना जैसी महामारी को पूरी दुनिया में फैलाने का अपराधी भी है। वह संकट की इस घड़ी में मानवता को बचाने की पहल के बजाय घटिया चिकित्सकीय उपकरण की सप्लाई कर पैसा कमाने में लगा हुआ है। किंतु भारत का चरित्र ऐसा नहीं है और संकट की इस घड़ी में भी हम दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। हमने अमेरिका से लेकर अपने तमाम पड़ोसी देशों को भी कोरोना की इलाज में काम आने वाली दवाइयां और जरूरी उपकरण भेज रहे हैं। एकात्म मानववाद को सूत्र वाक्य मानकर चलने वाली केंद्र की सरकार संकट की इस घड़ी में भी संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।

कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में हम अवश्य जीतेंगे। संसाधनों के अभाव के बावजूद जीतेंगे। यह जीत 130 करोड़ भारतवासियों के आत्मबल की जीत होगी। धैर्य की जीत होगी। परोपकार की भावना की जीत होगी। ❑❑

(लेखक एक कालेज में प्रिंसिपल और स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं।)

वैक्सीन क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा जरूरी

हाल के समय में कोविड–19 पर होने वाली व्यापक चर्चा में यह मुद्दा अधिक छाया रहा है कि इसके लिए वैक्सीन की कैसी तैयारियां हो रही हैं। इस चर्चा के साथ इस बारे में विचार करना भी बहुत जरूरी है कि इस समय विश्व स्तर पर वैक्सीन क्षेत्र में चंद बहुराष्ट्रीय कंपनियां कितनी हावी हो चुकी हैं। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कुछ अरबपतियों के साथ मिलकर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाए हैं जो वैक्सीन क्षेत्र पर पूरी तरह छा गए हैं।

कुछ गरीब और विकासशील देशों के बारे में यह कहा गया है कि वहां की वैक्सीन नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में उनकी अपनी सरकार का निर्णय उतना नहीं होता जितना कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों, इनके अरबपति मित्रों और इनके अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का होता है। इसका एक प्रतिकूल असर यह देखा गया है कि कई बार ऐसे बहुत महंगे उत्पाद इन देशों पर थोप दिए जाते हैं जिनकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। इस तरह इन देशों का स्वास्थ्य बजट अस्त–व्यस्त हो जाता है। इतना ही नहीं ऐसे अनेक देशों में देखा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वैक्सीन की सुरक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना विकसित देशों में दिया जाता है और इस कारण टीकाकरण के बाद अनेक लोगों विशेषकर बच्चों पर अनेक प्रतिकूल असर देखे गए।

सुरक्षा संबंधी मुद्दे कोविड–19 में तो और भी महत्त्वपूर्ण होंगे। सामान्यतः एक वैक्सीन दस से पंद्रह वर्ष में विकसित होता है पर कोविड–19 के वैक्सीन को 12 से 18 महीने में विकसित करने के प्रयास हो रहे हैं। इतनी शीघ्रता में कोई वैक्सीन आज तक विकसित नहीं किया गया। अतः इससे जुड़ी सुरक्षा के बारे में अधिक ध्यान देना जरूरी है। पहले जब भी ऐसी समस्याएं आईं हैं तो गरीब व विकासशील देशों के लोगों पर अधिक प्रयोग किए गए हैं। अतः इन देशों को सुरक्षा के बारे में अधिक सचेत रहना चाहिए। एक समय अफ्रीका के अनेक अखबारों में तो ऐसे सवाल उठे थे कि हमें गिनी पिग की तरह इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है।

इन बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विकासशील देशों में अनेक सहायक कंपनियां हैं। इन कंपनियों की नजर इस पर है कि विकासशील देशों के टीका कार्यक्रमों में उनके अधिक

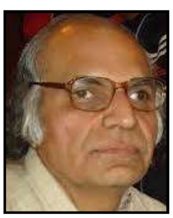

अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि वैक्सीन क्षेत्र की प्राथमिकताएं ठीक से तय की जाएं व इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महत्त्वपूर्ण व प्रमुख स्थान दिया जाए। आगामी दिनों में यह मुद्दे अधिक महत्त्वपूर्ण होते जाएंगे व यह बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाएगा कि वैक्सीन क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाए।

– भारत डोगरा

महंगे और मुनाफे वाले वैक्सीनों को किसी तरह शामिल करा लिया जाए क्योंकि यदि अनिवार्य टीकों में उनका महंगा टीका जुड़ गया तो बिना किसी विशेष प्रयास के उनके करोड़ों टीकों की बिक्री प्रतिवर्ष सुनिश्चित है। इसमें भी वे अधिक कम्बीनेशन के ऐसे टीकों को बेचने में अधिक रुचि रखती हैं जिनका पेटेंट अधिक समय तक चल सकता है व एकाधिकार जैसी स्थिति भी मिल सकती है।

एक अन्य प्रवृत्ति यह देखी गई है कि विकासशील देशों के कुछ अधिकारियों व विशेषज्ञों को भी यह कंपनियां व अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन प्रलोभन देने लगे हैं कि हमारी बात मानो तो तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अवकाश प्राप्ति के बाद मोटी आय का पद या अनुबंध मिल जाएगा।

इस तरह एक बहुत अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है कि टीकाकरण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अब निर्णय इस आधार पर नहीं लिए जा रहे हैं कि किसी देश में सबसे जरूरी व उचित लागत के टीके कौन से हैं अपितु यह महत्त्वपूर्ण निर्णय इससे प्रभावित हो रहा है कि बहुत साधान-संपन्न बड़ी कंपनियां व नसे जुड़े गठबंधन कौन से टीके बेचना चाहते हैं व उसमें सफल होते हैं।

विकसित देशों में कुछ नए टीके आए हैं पर वे महंगे हैं। अतः पता नहीं कितने टिक पाएंगे। यदि उन्हें विकासशील देशों के टीकाकरण में जगह मिल गई तो उनका उत्पादन कहीं बड़े पैमाने पर हो सकेगा व प्रति टीका लागत कम हो जाएगी। इस आधार पर टीका कंपनी का कारोबार टिक सकेगा।

अतः अनेक कंपनियों का प्रयास यह है कि जो टीके पहले से विकासशील देशों के टीकाकरण में लगे हैं उनमें कोई नया टीका जोड़कर अपना नया कंबीनेशन बना लें और इस नए कंबीनेशन को टीका कार्यक्रम में शामिल करा लें। इस तरह एक ही झटके में नए कंबीनेशन का आर्डर मिल जाता है और बहुत मुनाफा प्राप्त होता है।

टीकाकरण का क्षेत्र पूरी तरह स्वास्थ्य व बच्चों के हित को आधार बनाकर निर्धारित होना चाहिए व इसपर मुनाफे की प्रवृत्तियों को किसी भी हालत में हावी नहीं होना चाहिए। इसके निर्णय निष्पक्षता से केवल उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यों व अध्ययनों के आधार पर होने चाहिए। इन प्राथमिकताओं को ऊपर रखते हुए समग्र वैक्सीन नीति बनानी चाहिए।

टीकाकरण कार्यक्रम के विशेष महत्त्व को देखते हुए प्रायः यह माना जाता है कि टीकों या वैक्सीन के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए व अधिकांश टीकों का उत्पादन इन सार्वजनिक उद्यमों में होना चाहिए।

अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि वैक्सीन क्षेत्र की प्राथमिकताएं ठीक से तय की जाएं व इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महत्त्वपूर्ण व प्रमुख स्थान दिया जाए। आगामी दिनों में यह मुद्दे अधिक महत्त्वपूर्ण होते जाएंगे व यह बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाएगा कि वैक्सीन क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाए। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http://swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

महामारियों ने बदला है इतिहास

चौहदवीं सदी के पांचवे दशक के अंत से छठे दशक की समाप्ति तक प्लेग का तांड़व यूरोप में हुआ जिससे एक तिहाई जनसंख्या कम हो गई। ब्लैक ड़ेथ अर्थात ब्यूबोनिक प्लेग के कारण मजदूरों की संख्या कम हो गई और खेती पर अधिक मात्रा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा इससे पश्चिमी यूरोप के देशों की सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गयी जिससे आज की मजदूरी प्रथा ने जन्म लिया

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

वर्तमान में नवंबर–दिसंबर 2019 से चीन के वुहान शहर से शुरु हुई नोवेल कौरोना वायरस से उत्पन्न महामारी कोविद–19 ने संपूर्ण विश्व के 205 देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कोविद–19 महामारी का अभी तक कोई ईलाज चिकित्सा वैज्ञानिक नहीं खोज पाये है। बस मरीजों को तथा सामान्य जनता को यही बताया जा रहा है कि अपने शरीर में वायरसों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी पॉवर) को बढ़ायें और उसको ही बढ़ाने की कोशिशें हो रही है। इस महामारी में मरीज के फेफड़ों को वायरस के द्वारा जकड़ लिया जाता है तथा सांस अवरुद्ध होने से मरीज तड़फ–तड़फकर अपनी जान दे देता है। मरीज से वायरस का संक्रमरण दूसरे स्वस्थ्य लोगों को मरीज की सांस व सक्रंमित हाथों से लग जाता है जिससे वह भी 10–14 दिन में कोविद–19 का शिकार हो जाता है।

इससे पूर्व भी विश्व में हैजा, पोलियों, प्लेग, कालरा, फ्लू, मलेरिया इत्यादि महामारियों ने मुनष्य के जीवन को खतरे में ड़ालकर लाखों लोगों की जान ली है। शुरु–शुरु में इन महामारियों के ईलाज के लिए भी कोई टीका, दवाईयां, इंजेक्शन, जड़ी बूंटी नहीं होते है तथा मरीजों में इम्यूनिटी विकसित कर उन पर अंकुश महामारी फैलने के महीनों बाद लगाया जा सका है।

वर्ष 1347 में चीन के जहाज जब इटली के बंदरगाह के किनारे पंहुचे तो जहाजों से बीमार चूहे भी वहां उतर गये और इटली तथा यूरोपीय देशों में प्लेग फैल गया। 1911 में चीन में ही एक अनाम वायरस से मंचुरियन क्षेत्र में फैलकर तबाही मचायी थी तथा बीमारी से बचने के लिए लोगों ने स्वयं को घरों में कैद (लॉकड़ाउन) कर लिया था। वहां की समस्त आर्थिक गतिविधि, उद्योग व व्यापार बंद हो गये थे, यात्राएं बंद कर सीमाएं सील कर दी गई थी। लोगों ने मूंह पर मास्क लगाया, क्योंकि संक्रमण अधिक था और लाशों के ढ़ेर बदबू छोड़ रहे थे, परन्तु वर्तमान में विश्व की रफ्तार अधिक है और लोगों का एक दूसरे देशों में आना जाना निरंतर तीव्र गति से जारी रहता है तो अब कोरोना वायरस दो महीनों में ही

1918 में स्पेनिश फ्लू ने विश्व की कुल जनसंख्या का 2.5 प्रतिशत जनसंख्या को मृत्यु प्रदान कर दी थी अर्थात पांच करोड़ लोग मारे गये थे।

सम्पूर्ण विश्व में फैल गया तथा विश्व में ढ़ाई लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई तथा 33 लाख से अधिक ज्ञात व अज्ञात लोग सक्रंमित हो गये। यदि विश्व में लोगों का आना–जाना अधिक तीव्र गति से नहीं होता तो कौरोना वायरस सिमट कर रह जाता। कोरोना वायरस का प्रकोप विश्व के लोगों का जीवन बदल रहा है तथा उनके जीवन स्तर में व रहन–सहन के तरीके में बदलाव आ रहा है।

1918 में स्पेनिश फ्लू ने विश्व की कुल जनसंख्या का 2.5 प्रतिशत जनसंख्या को मृत्यु प्रदान कर दी थी अर्थात पांच करोड़ लोग मारे गये थे। भारत में 18 लाख लोग मारे गये जो विश्व में किसी भी देश का सर्वोत्तम आंकड़ा था। उस समय अंग्रेजों का शासन था तो इसलिए यह आंकड़ा बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि कुछ आंकड़े छुपाये भी गये होंगे। स्पेनिश फ्लू ने तीन हमले किये थे। 1918 के पहले तीन महीनों में इसका हल्का प्रकोप हुआ था, अगस्त 1918 के अंतिम हफ्ते में दूसरा प्रकोप हुआ और वर्ष 1919 के पहले महिनों में तीसरा प्रकोप हुआ जिसकी भयावता पहले व द्वितीय प्रकोप के बराबर ही थी। सितंबर से दिसंबर 1918 के 13 सप्ताह में सबसे ज्यादा लोग मारे गये थे। उस समय इस वायरस को पहचाना नहीं जा सकता तथा चिकित्सक परेशान हो गये। कोई दवाई व टीका नहीं, कोई एंटीवायरस अथवा एंटीबायोटिक नहीं। उस समय भी शारीरिक दूरी व क्वारंटाइन जैसे उपाय ही किये गये थे जो कि बहुत देर से उठाये गये कदम थे। रुस ने सर्वप्रथम केन्द्रीयक त हेल्थकेयर प्रणाली अपनायी उसके बाद जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने इस सोशलाइज्ड़ मेड़िसिन हेल्थकेयर प्रणाली को अपनाया। अमेरिका ने बीमा योजनाएं लागू की। 1920 में कई देशों ने अपने–अपने यहां स्वास्थ्य मंत्रालय गठित किये। लीग ऑफ नेशंस (अब संयुक्त राष्ट्र) ने वैश्विक स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु एक शाखा खोली जो आज का विश्व स्वास्थ्य संगठन बना। यह स्पेनिश फ्लू तथा कोरोना वायरस की तरह ही सांस से फैलते है तथा सतह को छूने से संक्रमण होता है। दोनों ही बहुत संक्रामक है। दोनों को ही क्राउड़ ड़िजीज अर्थात भीड़ का रोग कहते है। अतः 1918 में जन्मी इस महामारी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को जन्म दिया, बीमा स्कीम लागू हुई तथा देशों में स्वास्थ्य मंत्रालय बनाये गये। आज विश्व स्वास्थ्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1801 में हैती में गुलामों ने बगावत हुई तो गुलामों ने फ्रांस के साथ समझौता करके तुसैत लोवरतूर ने शासन संभाला। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने हैती में कब्जा जमाने के लिए भेजी गयी सेना में पीत ज्वर (यलोफीवर) फैल गया परन्तु उसका ईलाज बोनापार्ट के चिकित्सकों के पास नहीं था तो उसके बहुत से सैनिक मारे गये और हैती पर कब्जे का उसका अभियान फैल हो गया जिसके दो साल बाद ही फ्रांस ने 21 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन अमेरिका को बेच दी। जमीन की इस खरीद व बिक्री को लुईसियाना पर्चेज के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस जमीन खरीद से अमेरिका का क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया था।

1888 से 1897 के कार्यकाल में राइंड़रपेस्ट नाम के वायरस ने अफ्रीका के 90 प्रतिशत पालतू जानवरों को समाप्त कर दिया था। जिससे भूखमरी से प्रभावित हुई अफ्रीका की अर्थव्यवस्था से यूरोपीय देशों ने वहां अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। 1900 तक अफ्रीका के लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र पर यूरोपीय देशों ने नियंत्रण कर लिया था यदि यह राइंड़रपेस्ट वायरस नहीं आता तो आज अफ्रीका की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती।

पन्द्रहवीं सदी के अंत में अमेरिकी महाद्वीपों में यूरोपीय देशों ने प्रसार किया तो वहां हैजा, मलेरिया, प्लेग, चेचक, खसरा, काली खांसी व मियादी बुखार ने अमेरिका के करोड़ों लोग मौत के शिकार हो गये। अमेरिका में जनसंख्या कम होने से जमीन का बड़ा हिस्सा चारागाह तथा जंगल में बदल गया था। कार्बन ड़ाईआक्साइड़ का स्तर कम होने से वहां तापमान गिर गया और लघु हिमयुग देखा गया।

पूर्व में जो महामारियों आयी उनसे भी मनुष्यों का जीवन बदल गया। विभिन्न साम्राज्य तबाह हो गये। विभिन्न साम्राज्यों का विस्तार व सुकंचन दोनों ही हुआ। वर्ष 1641 में उत्तरी चीन में प्लेग फैल गया था ऊपर से सूखे व टिड्डियों का प्रकोप हुआ तो लोगों के पास अनाज ही समाप्त हो गया था

ऊपर से विदेशी आक्रमणकारियों ने चीन से मिंग राजवंश को समाप्त कर दिया। मंचूरिया के किंगवंश के राजाओं ने राज किया अर्थात अप्रत्यक्ष रुप से प्लेग जैसी महामारी ने चीन के मिंग राजवंश को ही उखाड़ फैंका था। बीमार व हारी थकी जनता सब देखते ही रह गयी थी।

चौहदवीं सदी के पांचवे दशक के अंत से छठे दशक की समाप्ति तक प्लेग का तांड़व यूरोप में हुआ जिससे एक तिहाई जनसंख्या कम हो गई। ब्लैक ड़ेथ अर्थात ब्यूबोनिक प्लेग के कारण मजदूरों की संख्या कम हो गई और खेती पर अधिक मात्रा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा इससे पश्चिमी यूरोप के देशों की सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गयी जिससे आज की मजदूरी प्रथा ने जन्म लिया तथा ये पश्चिमी यूरोप के देश नकदी आधारित अर्थव्यवस्था अपनाने लगे। आर्थिक रुप से सम्पन्न हुए इन देशों ने समुद्री यात्राओं से साम्राज्यवाद को प्रारम्भ कर दिया। जब पश्चिमी यूरोपीय देश अन्य देशों में गये तो वहां शासन के लिए कब्जा करके उपनिवेशवाद शुरु हो गई और पश्चिमी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो गई। इससे अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हो गया और उद्योगों ने उत्पादन की नई नई तकनीकें विकसित करनी शुरु कर दी। इससे पश्चिमी यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति भी

महामारियां जब फैलती है तो वे ईलाज उपलब्ध न होने के कारण तेजी से फैलती है परन्तु प्रयोगशालाओं में उनके लिए ईलाज भी तलाश कर लिया जाता है।

मजबूत हो गई। यूरोपीय देशों ने अन्य देशों को अपना उपनिवेश बनाकर उनके शोषण का कार्य शुरु कर दिया। इससे विश्व में बहुत से यूरोपीय देशों का दबदबा हो गया और वे स्वंय विकसित देश कहलाने का गौरव प्राप्त करने लगे।

यह भी देखा गया है कि सक्रंमित बीमारी से लोगों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। कोरोना वायरस से भी दो–तीन साल में हर्ड़ इम्यूनिटी विकसित हो सकती है। इस वायरस का प्रकोप गर्मी के मौसम में कम हो जाता है तथा सर्दी के मौसम में यह पुनः जागृत हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकड़ाउन से कोरोना वायरस का संक्रमण कम होता देखा जा रहा है इसमें फिजिकल ड़िस्टेंसिंग व मास्क उपयोगी सिद्ध हो सकते है। महामारियां जब फैलती है तो वे ईलाज उपलब्ध न होने के कारण तेजी से फैलती है परन्तु प्रयोगशालाओं में उनके लिए ईलाज भी तलाश कर लिया जाता है परन्तु इतना जरुर है कि महामारी के दौरान लोगों की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्रियाकलापों के साथ उनके रीति रिवाज, विभिन्न रस्में, रहन सहन का स्तर तथा लोगों का सोचने का ढ़ंग एकदम बदल जाता है। हम सामूहिक होकर बहुत से रीति रिवाज व रस्म निभाते है, हो सकता है कि कोरोना वायरस के भय के कारण लोगों में सामूहिकता व सामाजिकता कम हो जायें, जहां वे एक प्लेट व बर्तन में आठ–दस लोग खाना खा लेते थे व एक बर्तन से ही मूंह लगाकर पानी पी लेते थे, इकट्ठे होकर दैनिक प्रार्थना करते थे, शादी व ब्याह इत्यादि में भारी मात्रा में लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता था, अर्थी व जनाजे के पीछे सैंकड़ों लागे चलते थे। अब हो सकता है कि लोगों की सोच में परिवर्तन हो जाये। शादी व ब्याह व रीति रिवाजों पर जहां व्यय की मात्रा कम होगी तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा ही। लोग अनुशासित होकर इस कोरोना वायरस से लड़ें तो उससे इस पर निश्चित रुप से विजय प्राप्त हो सकेगी। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

ठेंगडी जी के विचारों में है भारत के आर्थिक विकास का सूत्र

एक मई का दिन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष भारत के अर्थ–संबंधित चिंतन के मनीषी श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी जी का जन्म–शताब्दी वर्ष भी है। इसलिए, मजदूरों के उस महान संगठनकर्त्ता के विचार स्वाभाविक रूप से मन में आते हैं। आज के दिन हम उनके विचारों का मूल्यांकन करें तो हम यह पाते हैं कि उन्होंने आधी सदी मजदूरों के बीच काम करके जो अनुभव प्राप्त किये और उन अनुभवों के आधार पर जो विचार दिए, वे हमारे लिए अनुपम धरोहर हैं। वे जिस काल में चिंतन कर रहे थे, उस समय मजदूर वर्ग को मार्क्सवादी विचारधारा का स्वाभाविक अनुयायी माना जाता था। लेकिन श्रमिक वर्ग और मालिक वर्ग के बीच स्थायी संघर्ष के सिद्धांत पर टिके मार्क्सवाद में अनेक व्यावहारिक दोष थे, जिसके दुष्परिणाम असंख्य देशों ने भुगते। 'संसार के मजदूर एक हो जाओ' का मार्क्स का नारा कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सका। दुनिया में जहाँ जहाँ मार्क्सवादी ट्रेड यूनियनवाद मजबूत हुआ, वहां उद्योग बंद हो गये।

पश्चिमी विश्व में मजदूरों के लिए कुछ गैर–मार्क्सवादी अन्दोलन भी हुए, परंतु, उनमें काम के घंटे या मजदूरी की कीमत आदि से आगे बढ़कर दूसरे मुद्दे नदारद थे। असल में पश्चिम की आर्थिक विषयों पर सोचने की दृष्टि ही खंडात्मक है। वह मजदूर को समाज के अभिन्न हिस्से के रूप में देखने के बजाय, मजदूर को एक अलग वर्ग के रूप में देखता है। इसीलिए वहां 'चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो' जैसे नारे शुरू हुए। दत्तोपंत जी मजदूरों को समग्रता की दृष्टि से देखते थे। वे इस तरह के नारों का विरोध करते थे, उनका मानना था कि मजदूर एक राष्ट्र का भाग है, वह अपने हित के लिए इतने अंधे नहीं हो सकता कि किसी भी कीमत पर समाज और राष्ट्र से अपनी बात मनवा लें। उन्होंने 'राष्ट्रहित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम' का नारा लगाया। मजदूर हित राष्ट्रहित में ही समाविष्ट हो, इसका उन्होंने पूरा प्रयास किया। वे जानते थे कि भारत का मजदूर अपने औजारों, मशीनों और वाहनों की भी पूजा करता है। उसके लिए फैक्ट्री सिर्फ कार्यस्थली ही नहीं है बल्कि उसकी पूजा स्थली भी है। बेवजह के राजनीतिक कारणों से होने वाली हड़ताल और तालाबंदी से मजदूरों को दुःख पहुँचता है। वे जानते थे कि यह 'श्रमेव जयते' में विश्वास करने वाला देश है। वह भारतीय मजदूर के सनातन मानस को समझते थे इसलिए उनका चिंतन सनातन मूल्यों पर ही आधारित था।

दत्तोपंत जी का कहना था कि हम अपने गौरवशाली अतीत में झांक कर देखें तो यह दिखाई देगा कि भारत में स्वनियोजित कारीगरी की एक ऐसी स्वयंपूर्ण स्वस्थ्य व्यवस्था थी, जिसके कारण हर श्रमिक आत्मनिर्भर और ससम्मान समाज में प्रतिष्ठित था।

– **श्रीनिवास**

दत्तोपंत ठेंगडी जी इस बात को काफी पहले ही समझते थे कि किसी भी दिन को मजदूरों का विशेष दिन घोषित कर देने से भारत के मजदूर उसे अपना लेंगे यह संभव नहीं। उनका मानना था कि भारत की सामाजिक–सांस्कृतिक परंपरा में श्रम और श्रमिकों के लिए सदैव विशेष आदर का स्थान रहा है। श्रमिकों–शिल्पकारों और मिस्त्रियों को भारतीय समाज भगवान विश्वकर्मा का रूप मनता रहा है, और विश्वकर्मा पूजन के लिए नियत दिन 17 सितम्बर पहले से ही मजदूरों के लिए विशेष दिन है। अतः भारतीय मजदूरों के लिए वही दिन मजदूर दिवस है।

दत्तोपंत जी द्वारा स्थापित संगठन भारतीय मजदूर संघ ने, जो कि आज देश का सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन है, जब 17 सितम्बर के विश्वकर्मा पूजन को मजदूर दिवस के रूप

में मनना शुरू किया। तो वामपंथ की विचारधारा मानने अकादमिकों और पत्रकारों को आश्चर्य हुआ। 1970 के दशक तक, जब विश्वकर्मा पूजा का कार्यक्रम देश के हर कस्बे और गाँव तक फैलने लगा और वामपंथियों द्वारा प्रसारित 1 मई का मजदूर दिवस सिमटता चला गया तो वामपंथी जनों को गहरा झटका भी लगा। उन्होंने मीडिया, साहित्य और अकादमिक जगत पर कब्ज़ा जमाये बैठी अपनी लॉबी को सक्रिय करके यह दिखाने का प्रयास किया कि भारत की परंपरा तो विशुद्ध आध्यात्मिक रही है, अतः उसमें श्रम जैसे भौतिकता से संबंधित विषय को लेकर कोई चिंतन हो ही नहीं सकता, और इसी लिए संघ की प्रेरणा से विश्वकर्मा पूजा को ही मजदूर दिवस कहकर मनाना तर्कहीन है। बहुत हुआ तो वामपंथियों ने यह माना कि यदि भारत में थोडा बहुत भौतिकता पर चिंतन हुआ भी है तो वह या तो चार्वाक का अतिवादी चिंतन है, या कौटिल्य का राजनीति और राज्य संबंधित चिंतन!

अब आज तो यह सर्वमान्य तथ्य है कि वामपंथ की राजनीति भारतीय समाज के सांस्कृतिक सत्यों से घबराती है। विश्वकर्मा पूजन पर वामपंथियों का बिफरना इसी प्रकार की घबराहट का एक नमूना था। उनके जवाब में दतोपंत जी ने अपनी किताब 'थर्ड वे ' में लिखा है कि, "अव्वल तो वामपंथियों को यह ज्ञात ही नहीं था कि विश्वकर्मा कौन हैं, दूसरे– उन्हें यह भी नहीं पता था कि भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वकर्मा क्षेत्र भी होता है। चूँकि उनकी विचारधारा 19 सदी के पश्चिमी यूरोप की आर्थिक व्यवस्था की समझ पर आधारित थी, अतः उनमें स्वरोजगार व स्वनियोजित कारीगरी के क्षेत्र को समझ पाने की क्षमता नहीं थी– क्योंकि यह क्षेत्र ना तो निजी क्षेत्र है और ना ही सार्वजनिक क्षेत्र है, बल्कि यह तो जन क्षेत्र है"।

दत्तोपंत जी ने जब तर्कपूर्ण ढंग से यह लिखा कि भारत में भौतिकता पर चिंतन की एक सुदीर्घ और स्वस्थ्य परंपरा रही है तो वामपंथियों को दुखद आश्चर्य हुआ। दत्तोपंत जी ने कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के प्रथम श्लोक को अपने तर्क के प्रमाण स्वरुप प्रस्तुत किया, उस श्लोक में कौटिल्य ने 'पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा से संबंधित बृहस्पति, शुक्र और अन्य ऋषियों के चिंतन को संकलित करने की बात की है'। इससे यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य से पूर्व भी अर्थ पर चिंतन सामान्य था।

शुक्राचार्य की रचना में किसी वस्तु का मूल्य कैसे तय होगा इससे संबंधित श्लोक भी है– "येनं व्ययेन संसिद्धः तद्म व्ययम सत्य मूल्याकं" अर्थात किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्य उसके निर्माण में आये खर्च के बराबर होता है, लेकिन दूसरे कारकों के प्रभाव से उनका मूल्य बढ़ता और घटता है। वे कारक कौन से हैं इसका विवरण इस प्रकार है– "सुलभासुलभः वाच्य अगुणत्व गुणसंश्रयी यया कामन् पदार्थनाम् अर्घ हिनाधिकं भवेत्"।

भारत के सभी प्रदेशों में लोहे, मिट्टी, सोने, लकड़ी आदि का काम करने वाले कारीगर और श्रमिक स्वयं को विश्वकर्मा की परंपरा का वंशज मानते हैं। विश्वकर्मा सनातन धर्म के वैदिक देवता हैं। ऋग्वेद में पृथ्वी को मनुष्यों के योग्य बनाने के लिए विश्वकर्मा की स्तुति की गयी है। अथर्ववेद, वाजसनेय संहिता और पुराणों में उनका गौरवपूर्ण उल्लेख है। रामायण और महाभारत में भी उनको शिल्प, वास्तु और कला के चमत्कार के देवता के रूप में देखा जा सकता है।

दत्तोपंत जी का कहना था कि हम अपने गौरवशाली अतीत में झांक कर देखें तो यह दिखाई देगा कि भारत में स्वनियोजित कारीगरी की एक ऐसी स्वयंपूर्ण स्वस्थ्य व्यवस्था थी, जिसके कारण हर श्रमिक आत्मनिर्भर और ससम्मान समाज में प्रतिष्ठित था। स्वयं–रोजगार की समाज में प्रतिष्ठा थी। प्रत्येक परिवार का अपना एक स्वनियोजित उद्योग हुआ करता था और इस प्रकार के स्वनियोजित उद्योग में ना तो किसी का हस्तक्षेप होता था और ना ही किसी पर निर्भरता। श्रमिक स्वयं ही अपना मालिक था और मालिक स्वयं ही अपना श्रमिक। श्रमिकों की कुशलता पर बहुत जोर था।

आज की परिस्थियों में हम उस मॉडल को जस का तस पुर्नस्थापित नहीं कर सकते लेकिन हम उससे काफ़ी कुछ सीख ले सकते है। आज 'स्किल इंडिया' योजना या अल्पसंख्यक युवकों के लिए विशेष 'उस्ताद योजना' के तहत युवाओं को कुशल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे उन्हें स्वयं रोजगार के योग्य बनाने की सोच है। इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे युवा वर्ग में दत्तोपंत जी जैसे विचारकों की सोच और दर्शन का कितना प्रसार होता है।

कोरोना महामारी के बाद 'दुनिया की फैक्ट्री' के रूप में जाने जाने वाले चीन के प्रति अनेक देशों में रोष है। अतः चीन अब आगे विनिर्माण क्षेत्र में ज्यादा समय हावी रह पायेगा ऐसा संभव नहीं लगता। अनेक देश चीन में हुए अपने निवेश को निकालना चाहते हैं। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो इस दिशा में अपनी पहल भी शुरू कर दी है। इस परिस्थिति में फैक्ट्रियों के चीन से हटकर भारत में स्थापित होने की काफी संभावना है। इससे न सिर्फ भारत में नए उद्योगों आएंगे बल्कि उन उद्योगों पर आधारित दूसरे स्व–रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सरकारें अपने स्तर पर इस परिवर्तन की तैयारी कर रहीं हैं। भारत के युवाओं को भी इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपने मेधा और मेहनत के दम पर भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। ❑❑

(लेखक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय सह–संगठन मंत्री हैं)

कोरोना महामारी एवं जल संकट

विश्वव्यापी व्यथा के रूप में उपस्थित हुई कोरोना महामारी, जिससे समस्त मानव जाति अत्यंत आतंकित है। विकसित देश हताश है लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़े होने के बावजूद भारत उससे सफलतापूर्वक संघर्ष कर रहा है। किसी प्रकार की दवा उपलब्ध न होने के कारण उससे सुरक्षा हेतु व्यक्ति का आत्म संयम ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा वह निरंतर अपनी साफ सफाई करते हुए बार–बार साबुन से हाथों को धोकर उन्हें सेनेटराइज करें तथा दूसरे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। समस्त सरकारें तथा कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ रहे चिकित्सक कोरोना से बचाव हेतु यहीं दो उपाय ही सुझा रहे हैं – फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं बार–बार साबुन से हाथ धोना तथा उन्हें सेनेटराइज करना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो व्यक्ति के स्वयं के मन एवं इच्छा पर निर्भर करता है किंतु साफ सफाई और बार बार हाथ धोने की क्रिया व्यक्ति की इच्छा के साथ ही साथ जल की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है।

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा डॉक्टरों का यही कहना है कि जितना हो सके हाथ साफ रखने की कोशिश करें तथा साबुन एवं सेंनेटाइजर से अपने हाथों को साफ करते रहें। यद्यपि पृथ्वी का दो तिहाई भाग जल से आच्छादित है किंतु आज मानव को पीने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है। यूं तो पूरे देश में जल की कमी है अनेक शहरों में भूजल का स्तर ग्राउंड जीरो तक पहुंच गया है। ग्रीष्म ऋतु के आते ही पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर सामने आ गई है ऐसी स्थिति में जब लोगों को पीने का पानी ही मयस्सर नहीं है तो वह पर्याप्त पानी के अभाव में कोरोना वायरस से बचाव के लिएदिन में कम से कम 10–12 बार हाथ धोने के लिए 20–22 लीटर पानी की व्यवस्था चाह कर भी कहां से करेगा। प्रश्न है कि क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध है?

प्रकृति द्वारा प्रदत्त वर्षा की एक एक बूंद अनमोल है उसका संरक्षण कर भूगर्भ के जलस्तर में वृद्धि करते हुए जल समस्या का निदान प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा स्थिति में समस्या अत्यंत गंभीर होगी तथा एक एक बूंद के लिए संग्राम होगा जिसके जिसके लिए समाज ही स्वयं उत्तरदायी होगा।

– दिनेश प्रसाद मिश्र

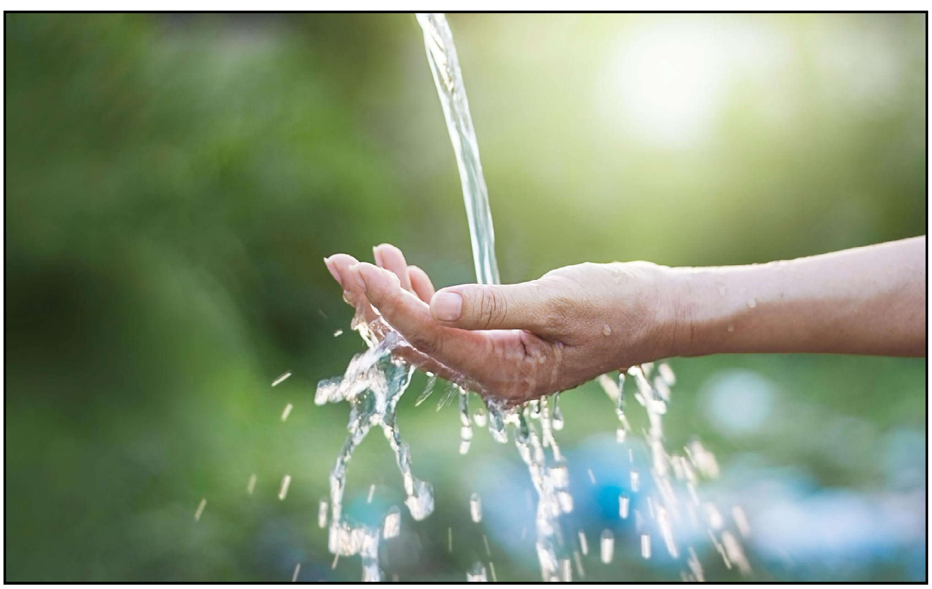

वस्तुतः भारत सहित विश्व का कोई भी देश पानी की समस्या से अछूता नहीं है सबको अपने नागरिकों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना पड़ता। भारत ही नहीं विश्व के अनेक देशों का जलस्तर अत्यंत नीचे जा चुका है और अनेक शहरों में जल का पूर्ण अभाव हो गया है। ऑस्ट्रेलिया का कैपटाउन पूरी तरह जल रहित बन चुका है वही स्थिति लगभग हमारे बेंगलुरु की भी है।

भारत के प्रमुख शहर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, बड़ोदरा, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, अमृतसर, लुधियाना, शिमला और बैंगलोर में पानी का स्तर अत्यंत नीचे जा चुका है। यहां के निवासियों को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पिछले 10 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूगर्भ का जलस्तर कम से कम 2 मीटर नीचे जा चुका है। फलस्वरूप देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी को उसकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है।

महाराष्ट्र, दिल्ली, बुंदेलखंड, राजस्थान आदि के अनेक शहरों में टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां टैंकरों के आते ही पानी के लिए लोगों की लंबी–लंबी कतारें लग जा रही हैं। राजस्थान के अजमेर में पानी के लिए संघर्ष में अप्रैल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है।

पानी की अनुपलब्धता या उसका अत्यंत सीमित मात्रा में प्राप्त होना जल समस्या का एक पक्ष है। कोरोना महामारी को देखते हुए जल समस्या का तत्काल निदान प्राप्त कर पर्याप्त जल तो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु सोच समझकर पानी का कम से कम प्रयोग कर अब भी काम चलाया जा सकता है। इसके लिए सीधे नल के पानी से हाथ न धोकर उसे मग या लोटे में लेकर कम से कम पानी का उपयोग करते हुए हाथ धोया जा सकता है।

कोरोना महामारी को देखते हुए जल समस्या का तत्काल निदान प्राप्त कर पर्याप्त जल तो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु सोच समझकर पानी का कम से कम प्रयोग कर अब भी काम चलाया जा सकता है।

विकास के नाम पर कंक्रीट के उग रहे जंगल, अनियंत्रित औद्योगिकरण तथा जल की अत्यधिक मात्रा के बलबूते पर तैयार होने वाली धान गेहूं जैसी फसलें भूगर्भ जल के अनियंत्रित दोहन को प्रोत्साहित करती है। अत्यधिक अर्जन, उपार्जन को दृष्टि में रखकर आवश्यकता से अधिक पानी का दोहन निरंतर किया जा रहा है।

आज समस्त विश्व आवागमन एवं संचार के संसाधनों में अभिवृद्धि होने के कारण एक गांव के रूप में बदल चुका है। विकसित देशों के हित सब पर भारी पड़ रहे हैं। अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए संघारक अस्त्रों के साथ ही साथ जैविक विषाणुओं का निर्माण कर उन्हें संघारक अस्त्रों के रूप में प्रयोग करने की भावना भी अनेक देशों में उत्पन्न हो गई है।

कोरनावायरस को भी चीन का सृजन माना जा रहा है। यह विषाणु मानवता के विरुद्ध प्रथम याअंतिम नहीं है, इसके पूर्व भी सार्स, मार्स आदि विषाणु सामने आ चुके हैं जिनमें बड़ी मुश्किल से नियंत्रण पाया जा सका था। अब आया कोरोना, जिस पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है तथा वह किसी के वश में नहीं आ सका है पूरे विश्व में हाहाकार मचाए हुए हैं, जब तक उसमें नियंत्रण प्राप्त करने हेतु दवाओं का आविष्कार नहीं हो जाता तब तक सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वयं की स्वच्छता अर्थात साबुन से बार–बार हाथ धोना तथा उन्हें सेनटराइज करना ही एक मात्र उपाय है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, सरकारों के निरंतर प्रयास से अपार धन जन की हानि होने के बाद कोरोना पर तो नियंत्रण पा लिया जाएगा किंतु पानी की समस्या का निदान तब भी नहीं होगा और आगे आने वाले दिनों में फिर इसी प्रकार के किसी अन्य वायरस या महामारी के आने पर पानी के लिए हाय तौबा मच जाएगा, उससे बचने के लिए आवश्यक है आज ही पानी की समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उसका स्थाई समाधान खोजा जाए और वर्षा जल को पूर्णरूपेण संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाए तथा वर्षा का एक जी बूंद वह कर व्यर्थ न होने पाए।

प्रकृति द्वारा प्रदत्त वर्षा की एक एक बूंद अनमोल है उसका संरक्षण कर भूगर्भ के जलस्तर में वृद्धि करते हुए जल समस्या का निदान प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा स्थिति में समस्या अत्यंत गंभीर होगी तथा एक एक बूंद के लिए संग्राम होगा जिसके जिसके लिए समाज ही स्वयं उत्तरदायी होगा। ❑❑

पृथ्वी दिवस की प्रतिज्ञा स्थायी और स्वदेशी पुनर्जीवन

हमारी पृथ्वी और हिंसा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। महामारी और बीमारियां प्रकृति की ओर से सुधर जाने की चेतावनी है। इससे पहले कि यह पृथ्वी नष्ट हो जाए हमें पर्यावरण को बिगाड़ने के मार्ग को छोड़कर एक नई अर्थव्यवस्था और नई दुनिया बनानी होगी।

22 अप्रैल लॉकडाउन का दिन नई दिल्ली और शायद दुनिया के लिए ऐतिहासिक माना जाये, क्योंकि 1970 के बाद यह सबसे स्वच्छ पृथ्वी दिवस होगा। जॉन मैककॉनेल, जिनकी याद में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विषैले बादलों और वाष्प में आई कमी को देख स्वर्ग में मुस्कुरा रहे होंगे। बढ़ी हुई ऑक्सीजन ने स्वर्गदूतों को भी खुशनुमा कर दिया होगा, लेकिन लौकिक घटनाएं एक तरफ, क्या हम अपने ग्रह का संरक्षण कर सकते हैं? प्रतिज्ञा करें कि हवा और पानी स्वच्छ रहे और अर्थव्यवस्था भी खिली रहे।

आत्म–निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 'प्रकृति पर विजय' पाने के उत्साह में हमने हमारे ग्रह–मंडल को विनाश के कगार पर ले आया है। मानव जीवन के लिए परमाणु युद्ध के बाद पर्यावरण का ह्रास होना, सबसे बड़ा खतरा है जिसका सबसे गंभीर परिणाम भू–राजनीति पर हो सकता है। नोअम चोमस्की ने हाल ही में लोकतंत्र पर बोलते हुए कहा कि जल संसाधनों को लेकर भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध भी कर सकते हैं। वैसे भी हमने बकरा तो हलाल कर ही दिया है और यह पृथ्वी और हिंसा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। महामारी और बीमारियां प्रकृति की ओर से सुधर जाने की चेतावनी है। इससे पहले कि यह पृथ्वी नष्ट हो जाए हमें पर्यावरण को बिगाड़ने के मार्ग को छोड़कर एक नई अर्थव्यवस्था और नई दुनिया बनानी होगी।

महात्मा गाँधी ने कहा था स्वदेशी अर्थव्यवस्था हमारे खून में है। इस पृथ्वी दिवस पर हम वसुधैव कुटुम्बकम की प्रतिज्ञा लें और विज्ञान के रास्ते पृथ्वी के पुनर्जीवन के पथ पर आगे बढ़ें।

– इन्द्र शेखर सिंह

हम यह नई दुनिया कैसे बनाएं? क्या हम भौतिक दुनिया का त्याग कर दें, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें, प्रौद्योगिकी से रहित जीवन चुन लें और जंगल में एक साधू का जीवन जीने लगें? नहीं। कोरोना वायरस हालांकि एक विकट आपदा है, लेकिन यह हमें अंधाधुंध खपत को कम करने और एक नए प्रतिमान को फिर से स्थापित करने का अवसर देती है, जहां हवा स्वस्थ हो, पानी साफ हो और पक्षी हमारे शहरों में फिर से गाते हो जाएं। जलवायु परिवर्तन और विनाश से बचने के लिए, हमें पांच सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है– कम उपभोग करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्जीवित करें, स्वदेशी और कृषि–पारिस्थितिकी को हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था में वापस ले आएं।

पिछली सदी के उत्तरार्ध में हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पृथ्वी के विनाश के लिए किया। अब हमें इन दोनों में दोस्ती कराने की जरूरत है। औद्योगिक क्रांति 4.0 को प्रदूषण मुक्त, चक्रीय और पुनर्जीवित करने वाली टेक्नोलॉजी से लानी होगी। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हो? हम इस यात्रा की शुरुआत अपने जीवन में पृथ्वी के बारे में जागरूकता लाने से करें। पृथ्वी सजीव है। वह केवल धूल और मिट्टी नहीं, पानी या पहाड़ नहीं, जिसका खनन

किया जाए। वह हमारे जरिए इस जीवित ग्रह में रहती है। हमें अपनी भूमि, अपने पहाड़ों या मिट्टी के साथ फिर से जुड़ना होगा और पृथ्वी के गुनगुनाते दिल को महसूस करना होगा। पृथ्वी जीवित है, और उसके दिए उपहार भी जीवित हैं, हमें उनका सम्मान करना होगा। एक बार यह चेतना हममें आ जाती है, तब हमारा अगला कदम इस ग्रह पर हमारी छाप को कम करना होगा। हमारे द्वारा खरीदी गई प्रत्येक क्रिया या उत्पाद का इस पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। फिर भी हमारी सफलता के सभी मानदंड जैसे कि बड़े घर, कई कारें, आदि पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। पानी, ईंधन और बिजली की खपत को कम करना न केवल 'स्मार्ट' है बल्कि किफायती भी है।

हमें विकल्प की खोज के लिए उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था को बंद करने की आवश्यकता है। पृथ्वी के पास सीमित संसाधन हैं और प्रत्येक अपव्यय के साथ हम भावी पीढ़ी के हक के संसाधनों को लूटते हैं। हमें उन उत्पादों को खरीदने या कम करने की आवश्यकता है जो अन्य मनुष्यों और ग्रह का शोषण करते हैं। याद रखें, हर बार जब आप कुछ खरीदते हैं तो सोचिये क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है? क्या यह मुझे और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है? उपभोग कम करने का सबसे आसान तरीका है वस्तुओं का पुनरुपयोग करना। हम इसकी शुरुआत बेकार में बहाए जाने वाले पानी को पौधों को सींचने में, कपड़ा धोने में, बर्तन साफ करने में कर सकते हैं या पुराने कपड़ों को रजाई बनाने में कर सकते हैं भारत चीजों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के नए नए विचारों से भरा है। व्यक्तिगत रूप से, हम कचरे को अलग करते हैं और हमने महीनों तक रसोई के कचरे को बाहर नहीं फेंका है, इसके बजाय हम खाद बनाते हैं या इसे सड़क पर गाय को खिलाते हैं। एक उर्वरक के रूप में मूत्र का शहरी बागानों के लिए पुनः उपयोग हो सकता है क्यों कि यह यूरिया और फॉस्फेट से समृद्ध है। किसी चीज के लिए जितना संभव हो उतना कम बिगाड़ हो सकता है, असंख्य पुनरावृत्ति हो सकती है, इसलिए कुछ फेंकने से पहले, एक मिनट रुककर सोचें कि आप इसे किसी अन्य तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं?

किसी दो नकारात्मक उपभोग को छोड़ने से पर्यावरण को एक बड़ा सकारात्मक लाभ हो सकता है। मनुष्य दुनिया के मालिक नहीं हैं, लेकिन प्रसिद्ध अमेरिकी संरक्षणवादी एल्डो लियोपोल्ड के शब्दों में, 'भूमि के चाकर' हैं। यह भूमि और धरती हमें अपने पूर्वजों से मिली है, लेकिन हमने केवल इसे हमारे वंशजों से उधार लिया है। यहां हमारा उद्देश्य हवा, पानी, मिट्टी को लूटना और तोड़ना नहीं है जबकि हम अपने घरों में एयर–प्यूरीफायर का आनंद लेते हैं। केवल कार्बन फुटप्रिंट के संदर्भ में कार्बन कमी, क्रियाओं/जलवायु क्रिया को देखना ही एकमात्र समाधान नहीं है।

महात्मा गांधी ने सौ साल पहले हमारे लिए समाधान की रूपरेखा तैयार की थी। उन्होंने इसे स्वदेशी अर्थव्यवस्था कहा था। यह एक ऐसी प्रणाली है जो आत्मनिर्भरता, प्रतिष्ठा और स्थानीय सहयोग पर आधारित है और पर्यावरण पर इसका न्यूनतम या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मॉडल बनाने की कल्पना की और लिखा कि "यदि आवश्यक हो तो वह पूरी दुनिया से अपना बचाव कर सकता है। यह अर्थव्यवस्था उत्पादन की विकेन्द्रीकृत प्रणाली पर आधारित थी, जो जरूत से ज्यादा उत्पादनों को दुसरे से साझा करती थी जो इसका उत्पादन नहीं कर सकती थी और वैसे ही दूसरों से लेती थी। यह समय है जब हम भारत में एक स्वदेशी 2.0 को स्वीकार करें जो पारिस्थितिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित हो। लेकिन क्या पर्यावरणवादी कृषि सक्षम हो सकती है? सीआईएमएमवाईटी के प्रधान वैज्ञानिक एम.एल. जाट का कहना है कि यह संभव है। उन्होंने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में लिखा है कि पर्यावरणवादी कृषि न केवल बेहतर स्वस्थ भोजन देता है बल्कि इससे हमारी खाद्य श्रंखला में रासायन और पेट्रोलियम पदार्थों की मात्रा भी कम हो जाती है। इस पद्धति की कृषि ने शुद्ध पानी, कम कार्बन फुटप्रिंट, सामान्य नाइट्रोजन साइकिल के साथ स्वादिष्ट खाद्य सामग्री का उत्पादन दिया है। तो हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें? अपने घर से शुरुआत करें। अपने किचन गार्डन में गमलों में धनिया और साग उगाये हाँ याद रखे कि आप किसी प्रकार के रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करें। ऐसी चीज़ उगाएं जिसे आप खाते हों। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो किसी ऐसे किसान का संपर्क करें जो आपके लिए सजीव खेती द्वारा कोई खाद्यान्न उगा सकें। जो शहर में रह रहे हैं वे शहरी बगीचों की वकालत करें जहां से हम अपने खाद्यान्न से समन्वय महसूस कर सकें और अपने बच्चों को बता सके की उनका खाना फ्रिज से नहीं बल्कि पेड़ पौधों से आता है। इन सभी सिद्धांतों के मूल में हरित अर्थतंत्र है जिसका आधार पुनर्जीवन, आर्थिक सशक्तिकरण और चक्रियता है। जब दुनिया आर्थिक अन्धकार में डूब रही है तब भारत को चाहिए कि वह टूटी आर्थिक और औद्योगिक व्यवस्था के मलबे में से बाहर निकलकर हरियाले अर्थतंत्र को अपना ले। जैसा कि महात्मा गाँधी ने कहा था स्वदेशी अर्थव्यवस्था हमारे खून में है। इस पृथ्वी दिवस पर हम वसुधैव कुटुम्बकम की प्रतिज्ञा लें और विज्ञान के रास्ते पृथ्वी के पुनर्जीवन के पथ पर आगे बढ़ें। ❑❑

(निदेशक– नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया)

https://www.etvbharat.com/hindi/delhi/bharat/bharat-news/weneed-a-permanent-and-indigenous-revival-to-safe-earth/na20200422091857563

कोरोना संकट एवं भारतीय संस्कृति

नवंबर 2019 में चीन के बुहान से चला कोरोना वायरस वर्तमान में विश्व के दो सौ से अधिक देशों मे फैल चुका है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा वैश्विक स्तर पर क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। विश्व की महाशक्ति अमेरिका में कोरोना ने जहां अफरातफरी मचा रखी है, वहीं यूरोप के कई प्रमुख विकसित देश इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। जिनमें इटली, स्पेन एवं ब्रिटेन की हालत सबसे ज्यादा खराब है। इन सबके बीच यदि भारत पर नजर डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की स्थिति अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की तुलना में अभी काफी बेहतर है।

विश्व के विकसित एवं तकनीकी रूप से दक्ष देशों की तुलना में भारत की जनसंख्या कई गुना अधिक होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के पीछे कई कारकों को ज़िम्मेवार माना जा रहा है। जिसमें भारतीय संभ्यता—संस्कृति में परंपरागत रूप से अपनाए जाने वाले कई क्रियाकलापों को इस वायरस से संक्रमण से बचाव के उपक्रम के रूप में विश्व स्तर पर काफी महत्व दिया जा रहा है। जिसे विश्व समुदाय ने काफी तेजी से आत्मसात करना प्रारंभ भी कर दिया है। जिसमें सबसे प्रमुख है भारतीय अभिवादन की परंपरागत पद्धति 'नमस्कार'। जिसमें कोई व्यक्ति सामने वाले के अभिवादन में दूर से ही अपने दोनों हाथ जोड़ता है। अभिवादन के इस भारतीय तरीके ने कोरोना महामारी के इस दौर में जहाँ सोशल डिस्टेंटिंग सबसे जरूरी है, विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा स्वीकारोक्ति पाई है। हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस चार्ल्स एवं विश्व के अन्य प्रमुख हस्तियों को हाथ मिलाने के स्थान पर 'नमस्कार' के माध्यम से लोगों का अभिवादन करते देखा गया। जिससे कोरोना के वर्तमान महामारी के दौर में अभिवादन की इस भारतीय पद्धति का व्यावहारिक महत्व बढ़ गया है।

कोरोना महामारी के इस दौर में इससे बचाव एवं इसके चलते उभरे मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा जिस जीवन पद्धति को अपनाने की बात कही जा रही है, उन सब क्रियाकलापों का समावेश भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में पहले से ही मौजूद है।

– डॉ. अजित कुमार

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंटिंग के साथ ही साथ दूसरे जिस चीज को सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है वह है व्यक्तिगत सफाई को बनाए रखना। जिसके

तहत हाथों की सफाई पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। अगर भारतीय परंपरा में हम देखें तो पाते हैं कि व्यक्तिगत सफाई को यहाँ प्रारंभ से ही काफी महत्व दिया गया है। भारत में 'स्नान–ध्यान' के बाद ही कुछ खाने–पीने को सही बताया गया है। बिना नहाये धोये खाने–पीने वाले को आलसी एवं निम्नस्तरीय किस्म का व्यक्ति घोषित किया गया है। इसके साथ ही साथ भारतीय परंपरा में बाहर से आने पर घर में प्रवेश के पूर्व जूते–चप्पल उतार कर हाथ–पैर अच्छे से धोने के पश्चात ही घर के अंदर प्रवेश का प्रावधान है। यहीं पद्धति बाहर से आने वाले अतिथियों के लिए भी अनिवार्य है। अगर भारतीय संभ्यता–संस्कृति में पाये जाने वाले इन परम्पराओं का वर्तमान कोरोना संकट से बचाव के उपाय के संदर्भ मे देखा जाय तो यह काफी वैज्ञानिक जान पड़ती है। जिसकी महत्ता पुनः सबके सामने है।

इन सबके साथ ही साथ कोरोना से बचने के लिए शारीरिक इम्यूनिटी का मजबूत होना चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य बताया जा रहा है। जिसके लिए खानपान में कुछ खास प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से विटामिन सी युक्त फल एवं सब्जियाँ तथा हल्दी, अदरक, लहसन, काली मिर्च इत्यादि का प्रयोग महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन सारे खाद्य पदार्थों का प्रयोग भारतीय समाज में बड़े स्तर पर की जाती है। शारीरिक इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बताए जा रहे हल्दी का प्रयोग भारतीय समाज में न सिर्फ खाने में मसाले के तौर पर बड़े स्तर पर किया जाता है बल्कि इसका प्रयोग सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी बड़े स्तर पर होता है। पारंपरिक भारतीय वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत जहां शरीर पर हल्दी लगा के की जाती हैं वहीं शुभ

कोरोना के इस संकट के दौर में सबसे अधिक खतरा बुजुर्गों के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि अधिक उम्र होने के चलते उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। अतः वायरस संक्रमण का ख़तरा भी उनको ज्यादा है।

कार्यों की शुरुआत के समय पहने जाने वाले वस्त्रों में हल्दी लगाकर उसे शुभ कार्यों हेतु तैयार किया जाता है। आज भी ग्रामीण इलाकों में शादी–ब्याह के अवसर पर घर के बुजुर्ग हल्दी लगा घोती पहन के ही कोई शुभ कार्य करते हैं। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए लगभग सम्पूर्ण भारत में हल्दी युक्त दूध पीने का प्रचलन है। इसके साथ ही साथ परंपरागत भारतीय चाय में अदरक एवं लौंग का प्रयोग सर्वविदित है।

भारत की प्राचीन योग–प्राणायाम से आज सारा विश्व परिचित है। कोरोना के इस महासंकट में आयुष चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञों ने योग–प्राणायाम को शरीर को आंतरिक रूप से मजबूत करने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकारोक्ति प्रदान करते हुये इसे शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला बताया है। इसके साथ ही साथ योग को मानसिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत करने वाली प्रक्रिया माना जाता है। जिसकी जरूरत कोरोना के इस संकट काल में अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है, जिससे बिना किसी पैनिक के इस महासंकट का सामना समाज कर सके। आज जब पूरी दुनिया घरों में बंद है एवं कई लोग एकाकीपन के चलते अवसाद ग्रस्त हो रहे हैं, इस स्थिति में योग एवं प्राणायाम की महत्ता और बढ़ गई है। जिसे अपनाकर एकाकीपन के चलते उभरे अवसाद को दूर किया जा सकता है। जिसे बड़े स्तर पर लोग अपना भी रहे हैं। वर्तमान दौर में योग एवं प्राणायाम की महत्ता ने निःसन्देह रूप से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे इस शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े क्रियाकलाप को विश्व स्तर पर स्विकारोक्ति दिलाने का काम किया है।

कोरोना के इस संकट के दौर में सबसे अधिक खतरा बुजुर्गों के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि अधिक उम्र होने के चलते उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। अतः वायरस संक्रमण का ख़तरा भी उनको ज्यादा है। इस स्थिति को देखते हुये विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा जारी दिशनिर्देशों में बुजुर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखने को कहा गया है। इस संदर्भ को यदि हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखें तो पाते हैं कि भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में सदैव बुजुर्गों के लिए आदर–सम्मान की बात कही गई है। जिसका पालन भी भारतीय समाज में बड़े स्तर पर किया जाता है। भारतीय संस्कृति में तो बुजुर्गों की सेवा को ईश्वर की पूजा से भी बढ़कर बताया गया है। तथा इसे अनिवार्य कर्तव्य घोषित किया गया है।

उपरोक्त संदर्भों को देखते हुये यह सहज ही कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी के इस दौर में इससे बचाव एवं इसके चलते उभरे मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा जिस जीवन पद्धति को अपनाने की बात कही जा रही है, उनसब क्रियाकलापों का समावेश भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में पहले से ही मौजूद है। जिसका परिणाम है कि इतनी सघन जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी भारत की स्थिति कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के मामले में अन्य देशों से काफी बेहतर है। ❑❑

(लेखक आईसीएसएसआर से संबंधित रिसर्च कार्य से जुड़े हैं।)

देश में मजदूरी दर में भिन्नता क्यों?

मजदूरी दर के निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत कहता है कि मजदूरों की मांग और मजदूरों की पूर्ति के आधार पर मजदूरी दर निर्धारित की जाती है। परंतु मजदूर को जीवन निर्वाह के लिये जितनी मजदूरी आवश्यक है उतनी मजदूरी तो श्रमिक को कम से कम मिलना चाहिए। ताकि श्रमिक की प्रतिदिन अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति हो सके। प्राचीनतम अर्थशास्त्रियों का मत भी था कि जीवन निर्वाह मजदूरी श्रमिकों को मिलना चाहिए। इसके लिए समय–समय पर जीवन निर्वाह के लिए मापदण्ड तय होना चाहिए।

कार्ल मार्क्स ने तो पूंजीवादी शोषण के विरूद्ध होकर ''दुनियाँ के मजदूर एक हो जाओ'' का नारा ही दिया था। जिससे कि मजदूरों का शोषण रूक सके। कार्ल मार्क्स के समय से अब तक संगठित क्षेत्रों में लगे श्रमिकों की स्थिति मजदूरी निर्धारण में ठीक हुई हैं परंतु असंगठित क्षेत्रों में लगे मजदूरों की स्थिति अभी भी पारिश्रमिक दरों में चिंताजनक ही कही जायेगी। न्यूट्रीशियन सुखात्ये ने 1974 में ग्रामीण व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी व्यक्तियों के लिए 2100 कैलोरी भोजन की बकालत की थी। ताकि लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सके। ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों ने कैलोरी का अंतर शारीरिक मेहनत के आधार पर रेखांकित किया गया था। इसी कैलोरी को भारत सरकार ने गरीबी रेखा के निर्धारण की सीमा बना ली। क्या केवल भोजन ही मात्र गरीबी रेखा का निर्धारण है? मेरे ख्याल से गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भोजन के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को भी सूचक बनाया जाना चाहिए साथ ही नये मानदण्डों को लेकर गरीबी रेखा को पुनः नये सिरे से परिभाषित किया जाना चाहिए।

योजना आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार कुछ समय पहले ग्रामीण और शहरों के लिए 27 और 32 रुपये प्रतिदिन के पारिश्रमिक का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था। वह तो

मजदूरी दर निर्धारण के जो नीतिकार हैं उन्हें मजदूरी दर की भिन्नता पर चिंतन करने की आवश्यकता है शहरी–ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की भिन्नता को खाद्यन्न, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवागमन के मानदण्डों के आधार पर निर्धारित करने की नीति बनाना चाहिए।

– **डॉ. जयप्रकाश मिश्र**

प्रतिदिन के पोषण के लिए ही पर्याप्त नहीं था। खाद्यान्न के अतिरिक्त बिजली, पानी, कपड़ा, दूरभाष, ईधन, आवागमन आदि का व्यय तो इसमें समाहित ही नहीं है।

जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल आबादी का 68.8 प्रतिशत भाग आज भी गांव में रहता है। नाबार्ड सर्वेक्षण के आधार ग्रामीण रहवासियों की औसतन आय 8059 रुपये मासिक बताई गई है। अर्थात् वार्षिक आय लगभग 96700 रु. है। जबकि शहरी प्रति व्यक्ति आय 279609 रु. आंकी गई है। निष्कर्ष इन तथ्यों से है कि ग्रामीण आय से शहरी व्यक्तियों की औसत आय लगभग 3 गुना अधिक है।

अर्थशास्त्री थामस पिकैटी ने अपने शोध में बताया कि 1980 से 2014 के 34 वर्षों में भारत में आर्थिक वृद्धि का 66 प्रतिशत भाग मात्र 10 प्रतिशत लोगों के पास चला गया और 29 प्रतिशत हिस्सा मात्र 1 प्रतिशत लोगों के पास चला गया। यह असमान वितरण है।

सरकार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए असंगठित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे। संगठित क्षेत्रों के लिए तो वेतन आयोग गठित किये जाते हैं उनकी सिफारिशें प्रत्येक दस वर्ष में लागू की जाती है। न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सरकार ने मजदूरों को भी चार वर्गों में विभाजित किया है– उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल। इन वर्गों के श्रमिकों की मजदूरी दर भी निश्चित की जाती है।

ग्रामीण और शहरी मजदूरी दर में भी अंतर देखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब मनरेगा योजना 2006 में प्रारंभ की गई तब 60 रु. मजदूरी दर थी। आज देश के विभिन्न राज्यों में अलग–अलग मजदूरी दरें हैं। केरल राज्य में मनरेगा में मजदूरी दर 271 प्रति दिवस है जबकि मध्य प्रदेश में 174 रूपये प्रति दिवस है। शहरी क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों की

कोरोना की विश्व स्तरीय बीमारी के कारण शहरों से लोग गाँव की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में गाँव में रोजी–रोटी की समस्या खड़ी हो जायेगी।

मजदूरी दर 318 रुपये प्रति दिवस है जो कलेक्टर दर पर जिले में निश्चित की जाती है। मध्य प्रदेश में कलेक्टर दर पर अकुशल श्रमिक को 318 रूपये प्रति दिवस मजदूरी निर्धारित की गई है। म.प्र. में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे मजदूरों को मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी और शहरी क्षेत्रों में मिलने वाली मजदूरी काफी भिन्नता है। कोविड–19 के संक्रमण के कारण भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर को रु. 202 कर दिया है।

इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि मजदूरी दर के निर्धारण में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिये जाते। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति दिवस चाहिए। जबकि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी चाहिए। ऐसी स्थिति में तो ग्रामीण क्षेत्रों की मजदूरी शहरी क्षेत्रों से अधिक होना चाहिए। जबकि मजदूरी दर भुगतान इसके बिल्कुल उलट है। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में मजदूरी दर 318 रुपये जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मजदूरी दर 174 रुपये हैं मजदूरी दर में ये भिन्नता आखिर क्यों है?

तथ्य बताते हैं कि संगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों का संगठन मजबूत है अपने अधिकारो के लिए लड़ते हैं। इस कारण प्रत्येक छः माह में कलेक्टर दर संशोधित होती रहती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कम उपलब्धता के कारण मजदूर आपस में संगठन नहीं बना पाते परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की मजदूरी दर में भिन्नता रहती है।

कोरोना की विश्व स्तरीय बीमारी के कारण शहरों से लोग गाँव की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में गाँव में रोजी–रोटी की समस्या खड़ी हो जायेगी। बाहर शहरों में रोजगार हेतु जो मजदूर पलायन करते हैं वह भूमिहीन मजदूर या सीमान्त कृषक इसीलिए शहरों की ओर पलायन करते हैं क्योंकि उनका वर्ष भर का रोजी–रोटी का जुगाड़ गाँव की खेती या मजदूरी से नहीं हो पाता।

इस संकट के समय में यदि 100 दिन के रोजगार को 200 दिन कर दिया जाये तब शायद मजदूरों को गाँव में रोजी–रोटी का जुगाड़ हो सकता है।

मजदूरी दर निर्धारण के जो नीतिकार हैं उन्हें मजदूरी दर की भिन्नता पर चिंतन करने की आवश्यकता है शहरी–ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की भिन्नता को खाद्यन्न, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवागमन के मानदण्डों के आधार पर निर्धारित करने की नीति बनाना चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी एवं मौसमी बेरोजगारी को ध्यान में रखकर मजदूरी दर का निर्धारण किया जाना चाहिए।❑❑

प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय महाराजा महाविद्यालय (छतरपुर म.प्र.)

प्रेस विज्ञप्ति

स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी और आत्मनिर्भरता हेतु जागृति और प्रतिबद्धता के लिए 'स्वदेशी स्वावलंबन अभियान' की घोषणा करता है। भारत के लिए आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल 'स्वदेशी' ही है। स्वदेशी उद्योग का कायाकल्प करके स्वावलंबन को प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें लघु उद्योग, लघु व्यवसाय, कारीगर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और अन्य गैर–कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीति निर्माताओं ने कभी भी स्वदेशी प्रतिभा, संसाधनों और ज्ञान पर भरोसा नहीं किया और इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र और बाद में विदेशी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर जोर दिया। पीएम मोदी का हाल ही में दिया गया वक्तव्य कि हमें स्थानीयकरण के लिए मुखर होना होगा, वैश्वीकरण और उदारीकरण, विशेष रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भर विकास की मौजूदा नीति के मॉडल में बदलाव की ओर इंगित करता है। यह उन स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने का समय है जो वैश्वीकरण के युग में नष्ट हो गए थे। यह उन आर्थिक नीतियों की शुरुआत करने का भी समय है जो मानव कल्याण, स्थायी आय, रोजगार सृजन में मदद करती हैं और सभी लोगों में विश्वास पैदा करती हैं।

स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करेगा। नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए कार्य किया जाएगा।

देश में 700 से अधिक एमएसएमई क्लस्टर हैं। इन समूहों का औद्योगिक विकास का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। चीन से अनुचित प्रतिस्पर्धा और अनुचित आयात नीतियों के कारण इनमें से कई औद्योगिक समूहों को भारी नुकसान हुआ। उन्हें हर तरह से समर्थन और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि वे न केवल रोजगार के अवसर पैदा करें बल्कि सबसे किफायती लागत में उच्च गुणवत्ता गवाले उत्पादों का भी उत्पादन कर सकें।

विनिर्माण क्षेत्र में भविष्य में ग्रोथ की शुरुआत के लिए पूरे देश में जिला स्तर पर ऐसे औद्योगिक समूहों की पहचान की जाएगी।

ग्रामीण शिल्प और कृषि आधारित उत्पाद भी भारत को स्वावलम्बी देश बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कृषि आधारित गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में असीमित अवसर उपलब्ध हैं, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पकड़ने, मशरूम की खेती, बांस की खेती, फूलों की खेती, बागवानी और अन्य शामिल हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास आज के समय की जरूरत है। इस 'स्वदेशी स्वावलंबन अभियान' के तहत एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है जिसमें श्रमिकों, किसानों, छोटे पैमाने पर उद्यमियों, एकेडमिशियन, टेक्नोक्रेट, उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों सहित सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। विभिन्न संगठनों और एसोसिएशनों के सहयोग से, हम लोगों तक पहुंच बनाएंगे। लोगों को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी उत्पादों की सूची वितरित करते हुए स्वदेशी के लाभों के बारे में जागरूक किया जायेगा।

यह स्थानीय, लघु स्तर के निर्माताओं, कारीगरों और छोटे व्यवसायों के उत्थान का भी समय है। इस उद्देश्य के लिए उद्योग, व्यापार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा।

स्वदेशी जागरण मंच पहले ही उद्योगों की समस्याओं की पहचान करने के लिए कई क्लस्टर अध्ययन कर चुका है। कई मामलों में स्वदेशी जागरण मंच का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण महत्व साबित हुआ है। इस तरह के अध्ययनों को घरेलू उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए एक मिशन मोड में कार्य किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के सफल प्रयोगों को ग्रामीण लोगों के बीच प्रचारित किया जाएगा ताकि वे खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित अन्य गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

हम सभी देशभक्त नागरिकों का आह्वान करते हैं कि वे पूरे जोश के साथ इस अखिल भारतीय स्तर पर 'स्वदेशी स्वावलंबन अभियान' में शामिल हों और मानवीय मूल्यों पर आधारित स्थानीय प्रतिभा, संसाधनों, ज्ञान, उद्यमशीलता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने के महान उद्देश्य के साथ इस अभियान को बड़ी सफलता दें; और स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्द्धन सुनिश्चित करते हुए, भारतीय विकास मॉडल के सिद्धांतों के आधार पर विकास में योगदान करें ताकि 'स्वावलंबन 'के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

हम सरकार से भी आह्वान करते हैं कि उपयुक्त आयात शुल्क संरचना द्वारा अनैतिक डंपिंग से घरेलू उद्योग का संरक्षण करे।

डॉ• अश्विनी महाजन (*राष्ट्रीय सह–संयोजक*)

प्रेस विज्ञप्ति

स्वदेशी जागरण मंच आत्मनिर्भरता हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए अखिल भारतीय 'स्वदेशी स्वावलंबन अभियान' की घोषणा करता है। भारत के लिए स्व–निर्भरता का अर्थ केवल 'स्वदेशी' ही है। स्वदेशी उद्योग का कायाकल्प करके स्वावलंबन को प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें लघु उद्योग, लघु व्यवसाय, कारीगर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और अन्य गैर–कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीति निर्माताओं ने कभी भी स्वदेशी प्रतिभा, संसाधनों और ज्ञान पर भरोसा नहीं किया और इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र और बाद में विदेशी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर जोर दिया। पीएम मोदी का हाल ही में दिया गया वक्तव्य कि हमें स्थानीयकरण के लिए मुखर होना होगा, वैश्वीकरण और उदारीकरण, विशेष रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भर विकास की मौजूदा नीति के माडल में बदलाव की ओर इंगित करता है।

यह उन स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने का समय है जो वैश्वीकरण के युग में नष्ट हो गए थे। यह उन आर्थिक नीतियों की शुरुआत करने का भी समय है जो मानव कल्याण, स्थायी आय, रोजगार सृजन में मदद करती हैं और सभी लोगों में विश्वास पैदा करती हैं।

देश में 700 से अधिक एमएसएमई क्लस्टर हैं। इन समूहों का औद्योगिक विकास का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। चीन से अनुचित प्रतिस्पर्धा और अनुचित आयात नीतियों के कारण इनमें से कई औद्योगिक समूहों को भारी नुकसान हुआ। उन्हें हर तरह से समर्थन और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि वे न केवल रोजगार के अवसर पैदा करें बल्कि सबसे किफायती लागत में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का भी उत्पादन कर सकें।

विनिर्माण क्षेत्र में भविष्य में ग्रोथ की शुरुआत के लिए पूरे देश में जिला स्तर पर ऐसे औद्योगिक समूहों की पहचान की जाएगी।

ग्रामीण शिल्प और कृषि आधारित उत्पाद भी भारत को स्वावलम्बी देश बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कृषि आधारित गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में असीमित अवसर उपलब्ध हैं, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पकड़ने, मशरूम की खेती, बांस की खेती, फूलों की खेती, बागवानी और अन्य शामिल हैं।

इस अखिल भारतीय स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के तहत एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है जिसमें श्रमिकों, किसानों, छोटे पैमाने पर उद्यमियों, एकेडमिशियन, टेक्नोक्रेट, उद्योग और व्यापार जगत के नेताओं सहित सभी लोगों को शामिल किया गया है। विभिन्न संगठनों और एसोसिएशनों के सहयोग से हम लोगों तक पहुंच बनाएंगे। लोगों को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी उत्पादों की सूची वितरित करते हुए स्वदेशी के लाभों के बारे में जागरूक किया जायेगा।

यह स्थानीय, लघु स्तर के निर्माताओं, कारीगरों और छोटे व्यवसायों के उत्थान का भी समय है। इस उद्देश्य के लिए उद्योग, व्यापार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा।

स्वदेशी जागरण मंच पहले ही उद्योगों की समस्याओं की पहचान करने के लिए कई क्लस्टर अध्ययन कर चुका है। कई मामलों में स्वदेशी जागरण मंच का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण महत्व साबित हुआ है। इस तरह के अध्ययनों को घरेलू उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए एक मिशन मोड में किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के सफल प्रयोगों को ग्रामीण लोगों के बीच प्रचारित किया जाएगा ताकि वे खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित अन्य गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

हम सभी देशभक्त नागरिकों का आह्वान करते हैं कि वे पूरे जोश के साथ इस अखिल भारतीय स्वावलंबन अभियान में शामिल हों और स्थानीय प्रतिभा, संसाधनों, ज्ञान, उद्यमशीलता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने के लिए एक महान उद्देश्य के साथ इस अभियान को बड़ी सफलता दें; और स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के आधार पर विकास में योगदान करें ताकि 'स्वावलंबन 'के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

डॉ॰ अश्विनी महाजन (*राष्ट्रीय सह–संयोजक*)

स्वदेशी जागरण मंच ने राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 'लोकल के लिए वोकल (स्थानीय उत्पादों का समर्थन करिए)' का मंत्र दिये जाने कुछ दिन बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की मंगलवार को घोषणा की। एसजेएम ने कहा कि वह आयातित वस्तुओं के विकल्प के तौर पर स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं की सूची बांटेगा। उसने घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयात शुल्क ढांचे में बदलाव की भी मांग की। कोरोना वायरस से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए देश में निर्मित उत्पादों का इस्तेमाल की पैरवी संबंधी मोदी के भाषण का हवाला देते एसजेएम संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा, 'यह वैश्वीकरण एवं उदारीकरण खासकर विकास के विदेशी पूंजी आधारित मॉडल पर आधारित वर्तमान नीति से सुखद विदाई है।'' उन्होंने कहा कि अपने 'स्वदेशी स्वालंबन अभियान' से मंच देश में'स्वेदेशी' एवं आत्मनिर्भरता के महत्व पर जागरूकता पैदा करेगा। महाजन ने कहा कि आत्मनिर्भरता छोटे उद्योगों, छोटे व्यापारियों, शिल्पियों और ग्रामीण उद्योगों समेत स्वदेशी उद्योग में जान फूंककर हासिल किया जा सकता है और उसका लक्ष्य रोजगार सृजन में रफ्तार के साथ ही समावेशी वृद्धि हो। देश में आयातित उत्पादों पर निर्भरता के लिए अतीत के नीति–नियंताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने स्वदेशी मेधा, संसाधनों और ज्ञान पर कभी भरोसा नहीं किया तथा विदेशी पूंजी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अत्यधिक बल दिया। महाजन ने कहा, ''हम स्थानीय मेधा, संसाधनों, ज्ञान, उद्यमिता और मानव मूल्यों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सभी देशभक्त नागरिकों एवं उद्योग से इस स्वदेशी स्वालंबन अभियान ' से उत्साह से जुड़ने का आह्वान करते हैं।''

https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/swadeshi-jagran-manch-announces-nationwide-campaign-for-local-industries-products/articleshow/75829169.cms?utm_source=Whatsapp_Wap_stickyAS&utm_campaign=nbtmobile&utm_medium=referral

विश्व व्यापार संगठन पर भारी पड़ता लोकलाईजेशन!

दुनिया भर में करोनो महामारी की हलचलों के बीच बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली (डब्ल्यूटीओ) में भी उथल–पुथल मची है। हालिया उठापटक में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अजबेदो के समय से पहले त्याग–पत्र देने से व्यापार जगत अचंभित है। अटलांटिक काउंसिल में वैश्विक व्यापार कार्यक्रम के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे विश्व व्यापार संगठन के लिए एक झटका बताया है। वहीं अमरीका के साथ–साथ भारत के आर्थिकी के जानकार मंशा जाहिर कर रहे हैं कि अजबेदो का त्याग–पत्र अमरीका और भारत के लोकलाईजेशन का परिणाम तो नहीं?

62 वर्षीय ब्राजीलियन अजेबेदो वर्ष 2013 से ही महानिदेशक है। अगस्त 2021 में उनका कार्यकाल समाप्त होना था, लेकिन समय से पहले ही जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में जुटी हुई है, उन्होंने एक आभाषी बैठक के दौरान नाटकीय तरीके से अपने त्याग–पत्र दिये जाने की घोषणा कर दी है। इसे लेकर दुनिया के व्यापार जगत के कान खड़े हैं।

हाल के वर्षों में अमरीका सहित दुनिया के कई देशों ने विश्व व्यापार संगठन पर किसी राजदूत के रूप में काम करने का आरोप लगाते हुए उंगली उठाई थी। मालूम हो कि वर्ष 2015 के दोहा दौर के बाद से ही संगठन द्वारा किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। आलम यह है कि दो सदस्य देश मछली पकडने के लिए सब्सिड़ी में कटौती के मुद्दे पर लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं लेकिन सहमति नहीं बन सकी। संगठन पर चीन के प्रति झुकाव का भी आरोप है। यही सब कारण है कि अमरीका, जापान, यूरोपीय संघ के साथ–साथ भारत जैसे देश भी डब्ल्यूटीओ में अधिक मूलभूत सुधारों पर जोर दे रहे हैं। इन देशों का कहना है कि व्यापार नियमों की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। आर्थिक क्षेत्र के कई जानकारों का यह मानना है कि पहले अमरीका और अब भारत ने जिस शिद्दत के साथ लोकलाईजेशन को आगे कर अपनी रणनीति तैयार की है, उसकी छाया संगठन पर सहज दिखाई दे रही है।

'स्वदेशी स्वावलंबन अभियान' से गांव में करेंगे रोजगार सृजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी मंत्र 'लोकल के लिए वोकल' के आह्वान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांवों में रोजगार पैदा करने की योजना तैयार की है। इस योजना को अभियान के तौर पर लागू करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) श्रमिकों, किसानों, उद्यमियों, शिक्षाविद, तकनीक के जानकार, उद्योग व व्यापार जगत के प्रतिनिधियों सहित सभी संबंधित लोगों को लेकर जिलास्तर पर समितियों का गठन करेगा। इसके साथ ही स्वदेशी अनुसंधान व तकनीक को धार देने की कोशिश होगी।

स्वदेशी के मॉडल में गांवों को शिल्प और कृषि आधारित उत्पाद से स्वावलंबी बनाने की मुहिम होगी। इनमें खाद्य

प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पकड़ने, मशरूम, बांस व फूलों की खेती, बागवानी समेत अन्य शामिल हैं। इनके लिए जरूरी तकनीक, कच्चा माल और बाजार की उपलब्धता के लिए सरकार के साथ सभी संबंधित लोगों से मदद ली जाएगी। ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए सफल लोगों की कहानी बताई जाएगी।

वहीं, विनिर्माण क्षेत्र में जिला स्तर पर औद्योगिक समूहों की पहचान की जाएगी। देश में मौजूद 700 से अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्लस्टर को फिर से खड़ा करने पर जोर होगा जो चीन से अनियंत्रित आयात के कारण अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके लिए कई क्लस्टरों का अध्ययन भी किया गया है। वहीं, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) गांव पहुंच रहे मजदूरों का डाटा तैयार कर उन्हें स्थानीय उद्योग में रोजगार उपलब्ध कराने समेत अन्य मदद करेगा।

एसजेएम के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि स्वदेशी का मॉडल गांवों से ही निकलेगा, अगर आजादी बाद देश में विकेंद्रीकरण की संकल्पना पर आधारित उद्योग तैयार किए गए होते तो आज मजदूरों की यह दर्दनाक तस्वीर सामने नहीं होती। बता दें कि कोरोना वायरस ने एक सबक तो जरूर दिया है कि आत्मनिर्भरता देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है और भविष्य में हम ऐसे लड़ाई के लिए भी तैयार हो पाएंगे।

https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-preparations-for-generating-employment-in-villages-in-india-jagran-special-20290556.html

स्वदेशी आंदोलन को घर–घर तक ले जाने की तैयारी

वैश्विक महामारी कोरोना को एक अवसर की तरह लेने के संघ प्रमुख मोहन भागवत के आग्रह के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं की पैरोकारी की है, उससे स्वदेशी जागरण मंच खासा उत्साहित है। रणनीतिक रूप से अब उसका स्वदेशी आंदोलन बदलाव का ठोस आग्रह करते दिख रहा है। ऐसे में उसने अपनी लड़ाई को और मुखर, व्यापक और सर्वग्राही बनाने की तैयारी की है, जिसमें उपभोक्ता, विक्रेता से लेकर उत्पादनकर्ता तक शामिल होंगे। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल कहते हैं कि अभियान का बड़ा चरण एक प्रकार से पूरा हुआ है, जब सरकार की ओर से इस तरह की बात ठोस तरीके से कहीं गई है। पर इस अभियान का यह 30 फीसद ही भाग है, 70 फीसद भागेदारी तो जनता की होगी। जब तक जनता की ओर से यह मांग नहीं आएगी कि हमें स्वदेशी ही चाहिए, तब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसलिए हम स्वदेशी आग्रह को व्यापक बनाना चाहते हैं, इसके लिए खरीदारों के साथ दुकानदारों और उत्पादनकर्ताओं तक पहुंच बनाएंगे।

मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक अरुण ओझा ने कहा कि इस अभियान में हम लोगों को इसके लिए भी जागरूक करेंगे कि कौन से उत्पाद देसी है, कौन से विदेशी। मतलब हम स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार में भी हाथ आजमाएंगे। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि वह अपनी मंशा को आगे बढ़ाते हुए हर सरकारी खरीद में स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें। इसे अनिवार्य किया जाएं। इससे स्वदेशी को बड़ा बल मिलेगा।

https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-swadeshi-jagran-manch-will-give-rise-home-goodsmovement-after-joining-the-government-20268310.html

आत्मनिर्भर भारत एक बेहतर कदमः स्वदेशी जागरण मंच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऐलान का स्वदेशी जागरण मंच स्वागत करता है। मंच के क्षेत्रीय विचार विभाग प्रमुख (बिहार, झारखंड) दिलीप निराला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के साथ हीं स्वदेशी जागरण मंच का 30 सालों का संघर्ष पूरा हुआ है। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत के सपने को लेकर मंच लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। प्रधानमंत्री ने इस अभियान के जरिए न सिर्फ एक लंबी आर्थिक छलांग का मंच तैयार किया है, बल्कि ज्यादा अवसरों को पैदा करने और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने का रास्ता भी तैयार किया है। अब लोगों के बीच स्वदेशी उत्पादों को लेकर भरोसा और मजबूत हो सकेगा और यहां के उत्पाद भी ग्लोबल ब्रांड के तौर पर स्थापित हो सकेंगे।

दिलीप निराला ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से भारतीय उत्पादों को दुनिया भर में सम्मान की नजर से देखा जाएगा। पीएम के 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा से समावेशी विकास का रास्ता खुलेगा। इस बार 1991 के उदारीकरण जैसा नहीं होगा, जिसके चलते शोषणकारी ग्लोबलाइजेशन की नीतियां लागू हुईं। इस पैकेज के जरिए नौकरियां देने वाली ग्रोथ हो सकेगी।

https://www.jagran.com/bihar/bhagalpur-swadeshi-jagran-manch-praised-pm-narendra-modi-20273692.html

चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान

कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में घिरे चीन के लिए भारतीय बाजार में भी बुरी ख़बर है। स्वदेशी जागरण मंच (स्वजामं) ने चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया है। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने आरोप लगाया है कि चीन की वजह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। जिसकी वजह से हमें घरों में कैद रहने पर मजबूर होना पड़ा है। साथ ही हजारों लोगों ने इस वायरस की वजह से अपनी जान गवाई हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि चीनी सामान की खरीदारी ना करें। सामाजिक बहिष्कार से ही चीन को समझाया जा सकता है। इसके लिए मंच ने रविवार (25 अप्रैल) को देशी संकल्प दिवस के रूप में मनाया।

डॉ. अश्वनी महाजन ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि चीन से फैले कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान हैं। इसकी वजह से इतना ही नहीं कि हम अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, लोग अपनी नौकरियों और व्यवसायों को खोने के कारण भी पीड़ित हैं और सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, जिससे दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि भारत प्रतिज्ञा लेगा कि तालाबंदी के दौरान और उसको हटाए जाने के बाद, हम चीनी उत्पादों का बहिष्कार जारी रखकर और भारतीय उत्पादों को खरीदकर अपने देश में समृद्धि वापस लाकर भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करेंगे।

https://www.abplive.com/news/india/swadeshi-jagran-manch-called-for-boycott-of-chinesegoods-beginning-of-swadeshi-sankalp-diwas-ann-1363460

स्वदेशी की परिकल्पना, दुनिया की नई वास्तविकता

'स्वदेशी' अब केवल स्वदेशी जागरण मंच का सिद्धांत ही नहीं रह गया है, जो अपनी स्थापना के बाद से भारतीय उत्पादों की पैरवी कर रहा है, बल्कि यह तेजी से एक जमीनी हकीकत बनता दिख रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) दोनों एक ही समय पर इस मुद्दे पर एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कोविड–19 के प्रकोप से बाजार के हालात को देखते हुए इसका मूल्यांकन किया जाना जरूरी हो गया है।

स्वदेशी के लिए स्वदेशी जागरण मंच की मांग बेशक आरएसएस के समर्थन में थी, लेकिन संघ ने इसे इतना स्पष्ट रूप से कभी नहीं दर्शाया है, कम से कम तब तक, जब कोरोना महामारी कहर बरपा रही है। हाल ही में एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष रूप से भारत में काम कर रहे विदेशी मीडिया को संदेश देते हुए आरएसएस के संयुक्त महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी न केवल भारत के लिए बल्कि महामारी के बाद दुनिया के सभी देशों के लिए नई वास्तविकता होगी।

स्वदेशी जागरण मंच के डॉ. अश्वनी महाजन के अनुसार, भारत में फार्मा कंपनियों के अधिग्रहण से नौकरियां नहीं पैदा होती हैं। उनका दावा है कि जब भारत में आने वाला एफडीआई अपने घरेलू बाजार को प्रभावित किए बिना यहां से निर्यात करना शुरू करता है, तो भारत को लाभ होता है। वर्तमान परिदृश्य में, कई कंपनियों ने भारत सरकार और राज्य सरकारों से संपर्क किया है।

https://hindi.newsd.in/mhaamaari-ke-baad-bhaartiy-baajaar-men-svdeshi-nee-vaastviktaa-bnkrubhregaaa/

स्वदेशी जागरण मंच का स्वदेशी संकल्प

छत्रपति शिवाजी की जयंती के अवसर पर पूरे भारत में स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया गया था, जिसे पूरे भारत में लोगों ने समर्थन दिया और स्वदेशी का संकल्प लिया। लोगों ने भविष्य में चीनी सामान न लेने का प्रण लिया। स्वदेशी जागरण मंच अमृतसर विभाग के विभाग संयोजक संदीप सलहोत्रा ने कहा कि अमृतसर विभाग में अमृतसर जिला तरनतारन और बटाला पुलिस जिला आता है।

बटाला के 4 नगरों फतेहगढ़ चूड़ियां, कादियां, बटाला और डेरा बाबा नानक में स्वदेशी संकल्प लिया गया, जबकि तरनतारन के तीन नगर रईया, जंडियाला गुरु और तरनतारन में स्वदेशी संकल्प लिया गया, जबकि अमृतसर जिले के अमृतसर महानगर के 10 नगरों ने स्वदेशी संकल्प में बढ़–चढ़ कर भाग लिया।

https://www.bhaskar.com/local/punjab/jalandhar/batala/news/swadeshi-jagran-manch-pledged-totake-things-made-in-the-country-127257770.html

चाहत से देसी, जरुरत पर स्वदेशी और मजबूरी में विदेशीः स्वजामं

आरएसएस प्रमुख मोहन भावगत के स्वदेशी सामानों को अपनाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से 'लोकल फॉर वोकल' की बात पर जोर दिया है। पीएम के इस आह्वान के बाद संघ और उसके समर्थक संस्थाएं अब लोगों ने लोगों से स्वदेशी वस्तुएं अपनाने पर जोर दे रही है।

स्वदेशी जागरण मंच ने गृह मंत्रालय की तर्ज पर रक्षा मंत्रालय की आर्मी कैंटीन और अन्य मंत्रलाय में भी स्वदेशी लागू करने की बात कही है। लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए घर–घर प्रचार करने से लेकर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की सूची भेजकर अपने अभियान से जोड़ने का काम शुरु कर दिया है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने दिप्रिंट से कहा, 'पीएम मोदी के भाषण का हम स्वागत करते है। स्वदेशी जागरण मंच वर्षों से कह रहा है कि देश का विकास तेजी से तभी होगा जब वह स्थानीय स्तर के आधार पर होगा।'

सेना की कैंटीन में भी लागू हो स्वदेशी

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने दिप्रिंट को बताया, 'पीएम के वोकल फॉर लोकल के आग्रह के बाद व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। अगर इसी तरह रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालय में भी ऐसा होता है तो अच्छा होगा। हमें बाहर से सामान मंगवाने की ज़रुरत नहीं है कि अब हम सब भारत में ही निर्माण कर सकते है।'

महाजन ने कहा, 'स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करने की बात हम कई दिनों से लोगों को कह रहे हैं। यह बात सभी लोगों के मन भी में भी है। हम चाहते हैं कि स्थानीय उत्पादों को भी आर्थिक सहयोग, मार्केट और तकनीक मिले। इसके लिए देश के करीब 700 औद्योगिक क्लस्टर से चर्चा कर हम सामाधान करेंगे। इन्हें हम तकनीक, आर्थिक सहयता संबंधित सहयोग करेंगे। 'इसमें स्वदेशी जागरण मंच सहित संघ के आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन भी आगे आकर काम करेंगे। हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे और सरकार का सहयोग भी लेंगे भी। स्वदेशी को लेकर हमारा कैंपेन कई दिनों से चल रहा है। अब हम जल्द जल्द लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए घर–घर प्रचार करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से लोगों को जोड़ेंगे। यह काम हमारा शुरु भी हो गया है।'

https://hindi.theprint.in/india/demand-local-avoid-imported-say-rss-swadesh-jagranmanch-just-likemodi/138731/

ट्रंप ने दी चीन को फिर धमकी

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने के मद्देनजर चीन से सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दी। जानलेवा संक्रमण ने दुनिया भर में तकरीबन तीन लाख लोगों की जान ले ली है, जिनमें 80,000 से ज्यादा अमेरिकी शामिल हैं। ट्रंप ने एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हम सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं।

पिछले कई हफ्तों से राष्ट्रपति पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है। सांसदों और विचारकों का कहना है कि चीन की निष्क्रियता की वजह से वुहान से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला है। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वह चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से फिलहाल बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि, उनके चिनफिंग से अच्छे रिश्ते हैं।

ट्रंप ने कहा कि चीन ने उन्हें निराश किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने चीन से बार–बार कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को वुहान की प्रयोगशाला जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन उसने इसे नहीं माना। ❑❑

https://24city.news/donald-trump-threatens-china-we-can-break-all-relations/

कोरोना महामारी के दौरान स्वदेशी जागरण मंच द्वारा सेवा कार्य

सचित्र झलक

स्वदेशी पत्रिका
डाक तिथि 15—16 मई 2020 नई दिल्ली पी.एस.ओ.
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2018-19-20
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

Swadeshi Activities

स्वदेशी संकल्प दिवस (25 अप्रैल 2020)

सचित्र झलक

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती